मूल्य : 25 रुपये
अक्टूबर - दिसम्बर, 2021

वर्ष : 10, अंक : 42

प्रेरणा दिवस - विशेषांक

नर्मदा समग्र

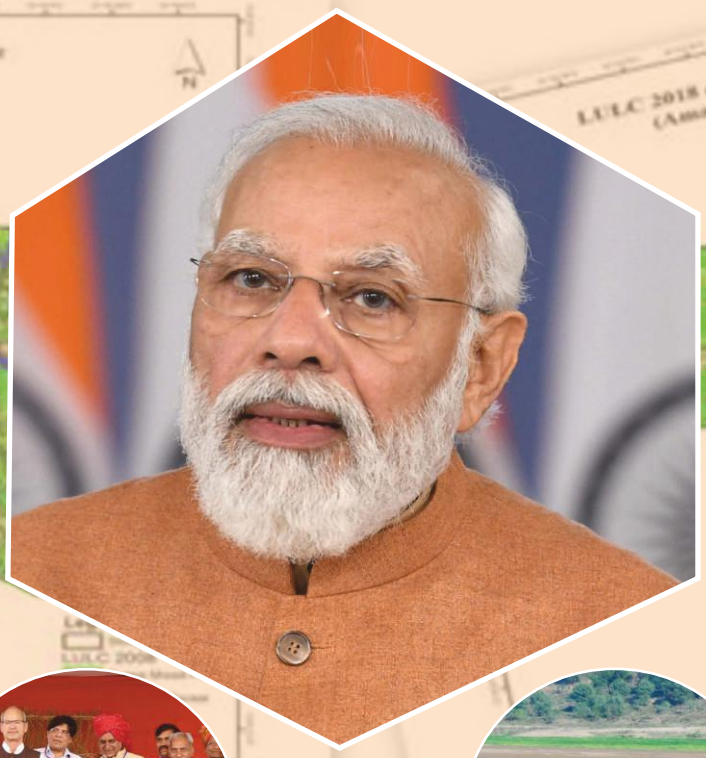

नर्मदा समग्र - प्रेरणा दिवस

अनिल माधव दवे जन्म जयन्ती (तिथिनुसार) - विजयादशमी

नर्मदा समग्र

का त्रैमासिक प्रकाशन

वर्ष : 10

अंक : 42

माह : अक्टूबर-दिसम्बर 2021

संपादक

कार्तिक सप्रे

संपादकीय मण्डल

डॉ. सुदेश वाघमारे

संतोष शुक्ला

आकल्पन

संदीप बागड़े/दीपक सिंह बैस

मुद्रण

नियो प्रिंटर्स

17-बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल

सम्पर्क

'नदी का घर' सीनियर एम.आई.जी.-2, अंकुर कॉलोनी,
शिवाजी नगर, भोपाल-462016

E-mail : narmada.media@gmail.com

@narmadasamagra @narmada_samagra

@narmadasamagra @narmadasamagra

@narmadasamagra www.narmadasamagra.org

इस अंक में .....

जीरो बजट कृषि वना जन आंदोलन

1. संपादकीय 05
2. धरती के तापमान का बेरोमीटर है नदियाँ 06
3. नर्मदा अंचल के वृक्ष - मुंडी 08
4. पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये अंकुर योजना 09
5. CECOEDECON सतत विकास की यात्रा 13
6. नर्मदा के गांधी 16
7. स्वर्णा की सुवर्ण आराधना 18
8. नर्मदा के उद्गम से ही शुरू हो रही नदी खत्म... 19
9. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन... 23
10. पानी के लिए होगा तीसरा विश्वयुद्ध ऐसा हर कहीं... 26
11. जोधपुर झालः जल भंडारण से आगरा की बुझेगी... 28
12. खेती को कैमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति... 30
13. सुभाष पालेकर कृषि जीरो बजट जन आंदोलन बना... 34
14. वैश्विक मंच पर एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा... 37
15. नदी एंबुलेंस - अनुभव कथन 39

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा नियो प्रिंटर्स, 17 बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं नदी का घर सीनियर एम.आई.जी.-2, अंकुर कॉलोनी, पारूल अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-462016 से प्रकाशित।

संपादक : कार्तिक सप्रे। फोन : 0755-2460754

नदियाँ

नदियाँ जीवन की धारा है,
बस पानी का भण्डार नहीं,
इस धारा में व्यवधान पड़े,
यह कुदरत को स्वीकार नहीं।

घटते जंगल, कटती मिट्टी,
सरिताओं में मल बहता है,
नदियों का पर्यावरण तंत्र,
सारी दुविधाएँ सहता है।

हम जुगत भिड़ाते रहते है,
नदियों से पानी लेने की,
कोशिशें नहीं क्यों होती हैं,
नदियों को भी कुछ देने की।

हम नदियों पर कितने निर्भर हैं,
क्या यह हमको पता नहीं?
सब जान रहे, पर चुप बैठे,
क्या इसमें कोई खता नहीं?

कुछ अपनी आदत को बदलें,
कुछ सेवा कुदरत की कर लें,
नदियों की हालत को समझें,
थोड़ी उनकी पीड़ा हर लें।

सारे कष्टों को सहकर भी,
जो अविरल बहती रहती है,
आईये जरा वह सुन लें,
जो 'नर्मदा' आपसे कहती है।

साभार - नर्मदा आप से कहती है...

सम्पादकीय

मानव जीवन को संभव बनाने वाले सभी जरूरी अवयव नदियों के आस-पास ही रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है क्योंकि नदियों के किनारे अन्न व खाद्यान्न उपजाने का तंत्र विकसित था। इस सहज़ उपलब्ध तंत्र पर जब 'मनुष्य' ने तकनीक का इस्तेमाल किया तो इससे उत्पादन तो बढ़ा मगर साथ ही मनुष्य की लालसा भी बढ़ती गई। जहरीले रसायनों से नदियाँ तो प्रदूषित हुई ही, साथ ही जमीन भी अपनी उर्वरकता भी खोती रही। इस ज़हरीले प्रदूषण का असर स्थानीय जैव विविधता पर भी पड़ा। नर्मदा सहित हमारे देश की नदियाँ साक्षी है कि कैसे मनुष्य ने धीरे-धीरे प्रकृति से सामंजस्य के साथ छेड़-छाड़ की ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नदी तंत्र को 'बीमार' बना दिया। आज आवश्यकता है कि नदियों के आस-पास का क्षेत्र समग्र रूप में विकसित हों। उसके लिए सबसे जरूरी है कि इस कार्य में नदी किनारे बसने वाले समुदाय के पास बिखरे स्थानीय ज्ञान को संरक्षित किया जाए और उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।

इस त्रैमासिक अंक में श्रद्धेय अनिल माधव दवे जी की तिथि अनुसार जयंती नर्मदा समग्र के संकल्प दिवस के साथ ही अमृतलाल वेगड़ जी की जयंती के दृष्टिगत नर्मदा क्षेत्र में हुए कार्यक्रमों और उन की स्मृतियों को लेख के रूप में लिया है। इस अंक में अनिल जी द्वारा पूर्व में लिखित आलेख 'धरती के तापमान का बेरोमीटर है नदियां' द्वारा जलवायु परिवर्तन से नदियों और जलाशयों पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य जनित गतिविधियों और समाज की सोच में होने वाले बदलाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से जो असंतुलन खड़ा हुआ है उससे पर्यावरण, जैव-विविधता, जलाशयों एवं स्वयं मनुष्य के स्वास्थ्य पर हो रहे परिणामों और भविष्य में होने वाली गम्भीर परेशानियों की ओर इंगित किया है। भारतीय पारम्परिक जीवनशैली, साहचर्य का भाव पुनः विकसित करने और नदियों के संरक्षण की दिशा में यह आलेख हम सबका मार्गदर्शन करता है।

विशेषांक के अगले लेख में मध्यप्रदेश शासन-प्रशासन के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पौधारोपण को प्रोत्साहन देने वाली 'अंकुर' योजना के बारे में विस्तृत चार्च की गई है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष से लगातार मुख्य मंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा रोपते हैं।

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद् स्व. श्री शरद जोशी जी एवं उनके द्वारा संस्थापित सिकोईडिकोन संगठन के माध्यम से विगत 35 वर्षों में जल संरक्षण-संचयन-प्रबंधन, पारिस्थितिक पुर्नजनन के प्रयासों और लोगों को जोड़ कर किए उल्लेखनीय कार्यों को चित्रण करता हुआ अगला लेख है। 'नर्मदा के गांधी' प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार व नर्मदा अनुरागी श्री अमृतलाल वेगड जी के जन्मतिथि पर उनकों याद करता हुआ लेख है जिसमें लेखक ने अपने अनुभव साझा किया हैं।

अंक के अगले लेख 'स्वर्णा की सुवर्ण आराधना' द्वारा हमारे जीवन में नदियों के महत्व को दर्शाते हुए कुछ माह पूर्व कर्नाटक के उड्डुपि जिले में स्वार्ण नदी के संरक्षण संवर्धन के लिए किए गए जनआंदोलन 'सुवर्ण आराधना' कार्यक्रम के बारे में बिंदुवार चर्चा करता है।

प्रकृति में मानवीय दखल, आधुनिकता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के कारण नर्मदा के उद्गम पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अनुसंधान उन्मुख लेख हमे सचेत करता है। इसके बाद का लेख चंबल नदी, उसके ईको-सेंसेटिव ज़ोन, जैव-विविधता को कायम रखने में आने वाली चुनौतियों और समृद्ध जीव संपदा के संरक्षण हेतु प्रयासों का विस्तार से वर्णन करता है। जल और नदियों के महत्व को दर्शाता आलेख 'पानी के लिए होगा तीसरा विश्वयुद्ध...', जंगल से जन्म लेने वाली नदियों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विषयों पर केन्द्रित है। इसके साथ ही हर अंक की तरह इस अंक में भी नर्मदा की एक सहायक नदी 'खुज' के बारे बताया गया है और उसी प्रकार नर्मदा अंचल के वृक्ष 'मुंडी' के बरे में बताया गया है।

आगरा में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जलाधिकार फ़ाउंडेशन द्वारा कृत्रिम झील पर किए प्रयासों का उल्लेख है। इसी अंक में नर्मदा समग्र द्वारा विगत कई वर्षों संचालित 'नदी एम्बुलेंस' पर एक अनुभव कथन भी प्रेषित किया गया है।

भारत के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों से पारम्परिक-प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया है। कृषकों को पारम्परिक-प्राकृतिक खेती के गुर बताता हुआ प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को विगत दिनों दिए उद्बोधन को लेख के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास इस अंक में किया गया है। इसी क्रम में प्राकृतिक शून्य बजट कृषि पर नर्मदा समग्र एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा एवं म.प्र. शासन के साथ भी आयोजित कार्यशाला के बारे में और म.प्र. में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में हो रहे प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करता एक आलेख है।

UNFCCC - COP26 जो कि इस वर्ष ग्लासगो में आयोजित हुआ उसके अनुभवों को साझा करता और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव एवं किए जा रहे प्रयासों व कार्यों के बारे में हमें जानकारी देता एक आलेख है।

हमारे प्राकृतिक संसाधन, खेती, आजीविका, जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहे हैं। इस अंक के सभी आलेखों, अनुभवों को अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें सामाजिक सहभाग, पारंपरिक पद्धतियाँ, प्राकृतिक परिवेश की महत्ता, इत्यादि बातों पर ज़ोर दिया गया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस वैश्विक संकट के समाधान सूत्र हमें देशज़ ज्ञान व परम्पराओं में मिल सकते हैं, जिनमें कि प्रकृति के साथ संगति रखते हुए जीवन-निर्वाह की दृष्टि दिखाई पड़ती है। □

धरती के तापमान का बेरोमीटर है नदियाँ

❑ अनिल माधव दवे

> "भारतीय संस्कृति में नदियों को बड़ी श्रद्धा से देखा गया है। उसे किसी कर्मकाण्ड के अन्तर्गत माता नहीं माना। बल्कि पर्यावरण व प्रकृति को स्वच्छ बनाय रखने के लिये उसे मइया जैसा श्रद्धा सूचक नाम व व्यवहार दिया। जो लोग नदी को दो किनारों के बीच बहता पानी मानते है वे भ्रम व भूल कर रहे हैं। वस्तुतः नदी की परिभाषा मे उसका सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र आता है। जहां बरसी हुई प्रत्येक वर्षा की बूंद बहकर नदी में आती हैं।"

जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण असंतुलन का विश्व रंगमच पर आज हो रहा हो-हल्ला आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। विश्व के तथाकथित सभ्य समाज ने जैसी दिनचर्या व जीवन रचना विकसित की यह सब उसका ही प्रभाव है। आज का शहरी नागरिक सुबह जगने के बाद के तीन घण्टे में औसतन पचास लीटर पानी खर्च कर देता है। भोजन व नाश्ता करते समय करीब-करीब 30 प्रतिशत खाद्यान्न सभ्य समाज जूठा छोड़ देते है। भोजनालय व भोजन की टेबल पर होने वाले अन्न अपव्यय के कारण पूरे विश्व में लाखों टन कार्बन का व्यर्थ उत्सर्जन होता है। नगरीय व्यक्ति लघुशंका जाने के लिये हर बार शौचालय मे औसतन 10 लिटर पानी खर्च कर देता है।

नलीय जीवन पद्धती (संगठित जल वितरण प्रणाली) ने छोटे मोटे नगरो व कस्बो से लगाकर बड़े-बड़े महानगरो में पानी की एक भूख खड़ी कर दी है। जो महाभारत की एक कथा की याद दिलाती है। जिसमें एक राक्षस को प्रतिदिन एक बैल गाड़ी अन्न, दो बैल और एक मनुष्य अनिवार्य रूप से खाने को लगता था। गाँव वाले प्रतिदिन मजबूरी में अपने में से एक-एक व्यक्ति को अनाज भरी बैल गाड़ी के साथ वहा पहुंचाते थे। इसी तरह आज की नगरीय रचना ने अपने आसपास के नदी तालाब व छोटे बड़े जल स्रोतो को मारना शुरू कर दिया है। जिन नदियों को समाज मार न सका (सुखा न सका) उसको उसने इतना गंदा कर दिया है कि अब वे नदियों के बजाय बहते हुय नाले बन गये है। हमारे शहर व नगरों के मध्य या आसपास से होकर जो बदबूदार नाला बह रहा है यथार्थ में कोई सौ वर्ष पहले वह एक स्वच्छ सुंदर नदी थी।

भारतीय संस्कृति में नदियों को बड़ी श्रद्धा से देखा गया है। उसे किसी कर्मकाण्ड के अन्तर्गत माता नहीं माना। बल्कि पर्यावरण व प्रकृति को स्वच्छ बनाय रखने के लिये उसे मईया जैसा श्रद्धा सूचक नाम व व्यवहार दिया। जो लोग नदी को दो किनारों के बीच बहता पानी मानते है वे भ्रम व भूल कर रहे हैं। वस्तुतः नदी की परिभाषा मे उसका वह सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र आता है, जहां बरसी हुई प्रत्येक वर्षा की बूंद बहकर नदी में आती हैं। इस भू-भाग में जो जंगल, खेत, पहाड़, बस्तियाँ, जानवर व अन्य सभी चल-अचल वस्तुएं है वे भी उसका शरीर ही है। इसमें निवासरत कीटपतंगों से

लगाकर बड़े-बड़े पहाड़ों तक से मानव जब व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसका सीधा प्रभाव नदी पर पड़ता है। चलते-चलते यह प्रभाव समान मात्रा में वहां निवास करने वाले लोगों पर भी पड़ने लगता है।

विश्व को सर्वाधिक आक्सीजन देने वाला अमेजन का घना जंगल राष्ट्रीय आय बढ़ाने के नाम पर दक्षिण अमेरिका में काटा जा रहा है। विश्व के वैज्ञानिक इसके दुष्प्रभाव की गणना कर समाज और सरकारों को चेतावनी दे चुके हैं। कम ज्यादा मात्रा में विश्व के अर्द्ध विकसित व विकासशील देशों का भी यही व्यवहार अपनी प्राकृतिक संपदाओं की ओर है। चिंता का विषय है कि पर्यावरण की मौलिक समझ का आज के अधिकतर योजनाकारों में भी अभाव है, जो विश्व-पर्यावरण संकट का प्रमुख कारण है। जबकि आज से चार सौ साल पहले शिवाजी महाराज अपने आज्ञापत्र (शासकीय आदेश) में स्पष्ट लिखते है कि - अनावश्यक रूप से कोई भी वृक्ष न काटा जावे, यदि अनिवार्य हो तो कोई बूढ़ा वृक्ष उसके मालिक की अनुमति के बाद ही काटा जावे।

UNFCC प्रतिवर्ष विश्व के किसी-न-किसी देश में जलवायु परिवर्तन पर एक पखवाड़े लम्बा अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। जी-7 जैसी महाशक्तियाँ व चीन, भारत जैसे उभरते देशों से लगाकर तुवालू (न्यूजीलैण्ड के पास का छोटा टापु देश) तक के राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। वहां पूरे समय गरमा-गरम बहस, वाद-प्रतिवाद व विचार-विमर्श होते है। पिछले पच्चीस-तीस सालों में यह प्रयत्न अगर किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है तो इसका एक मात्र कारण है, विश्व नायकों का प्राकृतिक संसाधनों की ओर देखने का सही दृष्टिकोण का अभाव! दृष्टि से ही व्यवहार और आचरण जन्म लेते है। अपरिपक्व दृष्टि शासन-प्रशासन में समाज संचालन के निरर्थक मार्ग तय करती है। जो सभी पर्यावरणीय संकटों की जड़ है।

पानी व कीटपतंगे बिगड़ते पर्यावरण से सबसे पहले प्रभावित होते है और अपने व्यवहार से उसे व्यक्त भी करते हैं। पृथ्वी पर तीन प्रकार का जल है- (1) समुद्र का खारा जल, (2) मीठा जल, (3) सूक्ष्म जल। पृथ्वी के पर्यावरण में बदलाव होने पर ये अपने-अपने प्रकार से प्रतिक्रिया करते है। जमा हुआ जल पिघलकर बहने लगता है। समुद्र में निरन्तर बहने वाली धाराओं की दिशा व तापमान में बदलाव आता है। कालान्तर में चलते-चलते समुद्र अपनी सीमा छोड़ने लगता है। यह सब, समुद्र संसार के छोटे-बड़े जीवों, वनस्पतियों व सतहों पर प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल के स्रोतों में भी यही परिणाम आते हैं। अगर हम राख/भस्म, धातु या जिवाश्म जैसे तत्वों को छोड़ दे तो कम ज्यादा मात्रा में सभी में जल का अस्तित्व होता है। यह जल अनुपात उसके अस्तित्व में प्रभावी भूमिका निभाता है। जल की मात्रा में हुआ परिवर्तन उसके स्वरूप को ही बदल देता है। प्रदुषण के कारण बदल रहा पर्यावरण इन तीनों जलों के वैश्विक अनुपात को तेजी से बदल रहा है। जो बीमार होती पृथ्वी का प्रतीक है।

पृथ्वी पर पिछले 150 वर्षों में तथाकथित विकास के नाम पर जो खराब होना था वह हो चुका! उस पर विलाप कर कुछ प्राप्त होने वाला नही है। अब समय सम्भलने व सुधरने का है। नदी को पूरी समग्रता से समझकर उसके सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र को स्वस्थ रखने का है। जिन्हें संस्कृति बचाना हो वह भी नदियों का संरक्षण करे, जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार जैसे मुद्दों पर प्रगति करना हो वे भी इस काम में प्रर्वत हो। जो विश्वशांति के पेरोकार है वे भी इस मंत्र का जाप करें क्योकी आने वाले युग में विभिन्न देशों के मध्य बहने वाली नदियां ही युद्ध व अशांति का कारण बनेगी। वस्तुतः पृथ्वी पर बहती हुई ये नदियां उसके देह पर लगे थर्मामीटर की तरह हैं जो निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदुषण व तापमान को दर्शाती हैं। नदियों के किनारे खड़े होकर या आसमान से देखकर हम उसके स्वास्थ्य को जान सकते है। यह समय कुंती (भारतीय दर्शन) के आदेश पर भीम बनकर भोगवादी आधुनिक जीवन-पद्धति रूपी राक्षस तक पहुंच, उसे समाप्त करने का है। यह जितनी जल्दी होगा नदियों के बहाने स्वयं को बचाने का कार्य हम उतना ही शीघ्र प्रारंभ होते देख सकेंगे। □

(नर्मदा समग्र के संस्थापक, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरणविद्, लेखक एवं चिंतक।)

“पृथ्वी पर पिछले 150 वर्षों में तथाकथित विकास के नाम पर जो खराब होना था वह हो चुका! उस पर विलाप कर कुछ प्राप्त होने वाला नही है। अब समय सम्भलने व सुधरने का है। नदी को पूरी समग्रता से समझकर उसके सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र को स्वस्थ रखने का है। जिन्हें संस्कृति बचाना हो वह भी नदियों का संरक्षण करे, जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार जैसे मुद्दों पर प्रगति करना हो वे भी इस काम में प्रर्वत हो। जो विश्वशांति के पेरोकार है वे भी इस मंत्र का जाप करें क्योकी आने वाले युग में विभिन्न देशों के मध्य बहने वाली नदियां ही युद्ध व अशांति का कारण बनेगी।”

नर्मदा अंचल के वृक्ष - मुंडी

कैम, कलम कदम्ब Mitragyna Parviflora कॉफी कुल RUBIACEAE

❑ डॉ. सुदेश वाघमारे

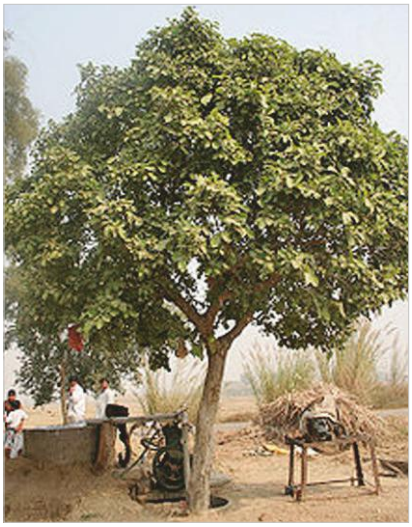

स्वभाव - भारतीय मूल का 25 मीटर ऊंचाई का वृक्ष पुराने वृक्ष के तने पर गांठे बन जाती है। अनुकूल वातावरण और मिट्टी मिलने पर सुंदर वितान बनाता है।

प्राकृतवास - काली और कछार की मिट्टी में बढ़िया विकास करता है।

छाल - चिकनी, पीली, भूरी, रन्ध्रयुक्त।

पत्तियाँ - नीचे से हृदयाकार और ऊपर से गोल, कुछ पत्तियों में नुकीला पर्ण अग्र। विपरीत जोड़े में नई पत्तियां गुलाबी पर्ण कलिकाओं से ढकी रहती है। जनवरी से मार्च तक पर्णपातन।

फूल - छोटे सफेद और सुगन्धित, 150 से 200 की संख्या में मुंडक पर निन्यस्त, दलपत्र 5, जायांग लम्बा और बाहर की ओर निकला हुआ। पुष्पन मई से जुलाई।

फल - मुंडक पर ही पकते हैं। पकने के बाद मुंडक काला दिखता है। विसरण के लिए बीज पंख युक्त होते है।

उपयोग - मध्यम श्रेणी की पीली-गुलाबी इमारती। उपकरण एवं खिलोने बनाने में उपयोग। पत्तियां उत्तम किस्म का पशु चारा।

औषधीय - जड़ एवं छाल का सत्व बुखार, पेट दर्द एवं मांसपेशियों के उपचार में।

रसायन शास्त्र - मिथाइल एसीटेट, कीटोन, टेनिन।

आई.यू.सी.एन. - पर्याप्त

भोपाल में कहां देखे - वन विहार बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास।

वानस्पतिक नाम Mitragyna में mitra का लैटिन अर्थ टोपी और gyn का अर्थ जायांग है जो इसके स्त्रीकेसर के आकार के कारण है। parviflora का लैटिन अर्थ 'छोटे फूल' होता है।

पुराणों में और धर्मग्रंथों में जिस कदम्ब का वर्णन है यह वही है। दूसरा उत्तर-पूर्व में नम भूमि में पाया जाने वाला वृक्ष भी कदम (Anthocephalous cadamba) के नाम से प्रसिद्ध हो गया है जो सही नहीं है। मथुरा, वृन्दावन के वन में और यमुना के किनारे मुंडी या कैम ही पाया जाता है जो भाषा वैज्ञानिक कारणों से कदम्ब का कैम हो गया है। कालिदास के काव्य में भी इसी का वर्णन है। कई ग्रामीण अचंलों में इसका प्रवेश द्वार बनाना अत्यंत शुभ मानते है। काले फल यानि मुंडक

इसकी पहचान हैं जो लगभग वर्ष भर पेड़ पर लगे रहते है। ❑

लेखक - सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
स्वतंत्र सलाहकार, राष्ट्रीय-अंर्तराष्ट्रीय
संस्थाओं से जुड़े हैं

पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये अंकुर योजना

राज्य का मुखिया यदि प्रकृति प्रेमी हो तो उसकी कार्यशैली में संवेदनशीलता दिखती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष यह है कि वे प्रकृति में अगाध श्रद्धा रखते हैं। रोज एक पौधा लगाने का संकल्प, नर्मदा की पवित्रता बचाने का संकल्प और हरियाली को सम्हालने का संकल्प, पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से अंकुर योजना आरंभ किा वृक्षारोपण के लिए जन-सामान्य को प्रोत्साहित किया। पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया। पेड़ प्राकृतिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से बड़ा कोई ऑक्सीजन संयंत्र नहीं है। भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूज्यनीय उन पर देवताओं का वास है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को पाँच वर्षों के अंतराल से एक पौधा लगाया चाहिये।

राज्य का मुखिया यदि प्रकृति प्रेमी हो तो उसकी कार्यशैली में संवेदनशीलता स्पष्ट दिखती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष यह है कि वे प्रकृति में अगाध श्रद्धा रखते हैं। रोज एक पौधा लगाने का संकल्प, नर्मदा की पवित्रता बचाने का संकल्प और हरियाली को सम्हालने का संकल्प इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने जन सहयोग से प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करना और पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से अंकुर योजना आरंभ किया। कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए जन-सामान्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। उनका मानना है कि हम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं लेकिन पेड़ प्राकृतिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों से बड़ा कोई ऑक्सीजन संयंत्र नहीं है। इस योजना के तहत वायुदूत ऐप पर अपना पंजीयन करा प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद उसकी दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रत्येक जिले से चुने गये विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार प्रदान करेंगे।

पौधे लगाने का नागरिक संस्कार

मत्स्य-पुराण में अद्भुत श्लोक है जिसमें वृक्ष को दस पुत्रों के समान बताया गया है। आज हमने मिलकर जो पौधे लगाये हैं वे कल वृक्ष बनेंगे और वर्षों तक हमारी रक्षा करते रहेंगे। नदी और पर्यावरण संरक्षण के लिये चलाये गये जन-अभियान को जनता का समर्थन मिला और अब यह लोक-व्यवहार में साफ दिख रहा है। मध्यप्रदेश सरकार को अंकुर अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें समाज की अगुवाई से पारीस्थितिकीय बदलाव लाने में सफलता मिलेगी।

शिवराज ने पौधे लगाने का जो नागरिक संस्कार देने की पहल की है वह लोगों को पर्यावरण के आध्यात्म से जुड़ने के लिये प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूज्यनीय है क्योंकि उन पर देवताओं का वास माना गया है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को पाँच वर्षों के अंतराल से एक पौधा लगाया चाहिये। 'भरत

पाराशर स्मृति' के अनुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगता है और उनका पोषण करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में श्रृक्षायुर्वेदश् का उल्लेख है। सम्राट बिंबसार के चिकित्सक जीवक को तक्षशिला में अध्ययन के अंतिम वर्ष में उनके शिक्षक ने ऐसी वनस्पति खोज लाने के लिये कहा जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। जीवक ऐसी कोई वनस्पति नहीं ढूंढ पाये। प्रत्येक पौधे में औषधीय गुण होते है। संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि उद्योग ऐसे पौधों पर ही टिका है।

मुख्यमंत्री बार-बार सार्वजनिक रूप से यह चिंता जाहिर की है कि हरित आवरण पर जैविक दबाव लगातार बढ़ रहा है। मानव बसाहट का विस्तार जंगलों तक पहुंच गया है। वन सम्पदा आधारित आजीविका के संसाधन कम हो रहे है। इस दृष्टि से बड़ी संख्या में पौधों का रोपण कर वन संपदा, नदियो, जल स्त्रोतो को समृद्ध बनाना अनिवार्य हो गया है। विनाश से बचने के लिये समाज को प्रकृति-आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुये वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा। उनका का मानना है कि नई पीढ़ी को नीम, आंवला, पीपल, बरगद, महुआ, आम जैसे परंपरागत वृक्षों की नई पौध तैयार करने की अवधारणा समझाना आवश्यक है। वनस्पतियों का जो सम्मान भारत भूमि पर है वह अन्यत्र नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों ने भी प्रकृति का आदर करना भारतीय धर्मग्रंथों और परंपराओं से ही सीखा है। यदि प्रकृति के अलौकिक स्पंदन और माधुर्य को अनुभव करना हो तो उसकी शरण में रहो। मनुष्य का वृक्षों से गहरा आत्मीय संबंध है। पौधों में मनुष्य के समान संवेदनाएँ होती हैं यह सिद्ध हो चुका है। मनुष्य के सभी धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कारों में वृक्षों की मंगलमय उपस्थिति है। कई भारतीय संस्कारों, व्रतों, त्यौहारों के माध्यम से वृक्षों की पूजा होती है। वृक्षों के नाम से कई व्रत रखे जाते है जैसे वट सावित्री व्रत, केवड़ा तीज, शीतला पूजा, आमला एकादशी, अशोक प्रतिपदा, आम्र पुष्प भक्षण व्रत आदि। 'मनु स्मृति' में वर्णित है कि वृक्षों में चेतना होती है और वे भी वेदना और आनंद का अनुभव करते है। समाज के गैर जिम्मेदार व्यवहार से यदि उनकी मृत्यु होती है तो समाज को उतना ही दुःख होना चाहिये जितना प्रियजन की मृत्यु पर स्वाभाविक रूप से होता है। □

आरंभ किया प्रदेश व्यापी अंकुर अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में जन-भागादारी से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस - 5 जून 2021 को प्रदेशव्यापी अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ की। इसमें वायुदूत एप भी लांच किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को एप पर रजिस्ट्रेशन कराकर स्वयं के द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है। लगाए गए पौधे की एक माह बाद पुनः फोटो अपलोड की जाना है। इनमें से चयनित प्रतिभागियों को प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्री चौहान द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के इन प्रयासों से प्रदेश में पौध-रोपण गतिविधि में विस्तार हुआ है। शासकीय कार्यक्रमों के साथ जन-सामान्य द्वारा अपने परिवार के शुभ आयोजनों और परिजन की स्मृति में भी पौध-रोपण किया जा रहा है। भेंट के रूप में पौधे देने का प्रचलन भी निरंतर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें भेंट में प्राप्त हो रहे पौधों का वृक्ष बैंक बनाने के का भी निर्देश दिया है।

'प्राणवायु पुरस्कार' क्या है?

जो लोग इस योजना में मध्यप्रदेश सरकार के साथ भाग लेना चाहते हैं वह अपना पंजीकरण वायुदूत एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं। इस योजना में मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को मुख्य रूप से पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एप्लीकेशन पर पंजीकरण के बाद उन्हें पौधा लगाते समय अपनी एक तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड करनी होगी कि वे पौधे की देखभाल किस तरह से करते हैं। उसकी सारी तस्वीर उन्हें लगभग 30 दिनों तक अपलोड करते जाना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले के चुने हुए कुछ प्रतियोगियों को विजेता के रूप में घोषित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। ''प्राणवायु पुरस्कार'' योजना में शामिल होने के लिए आज ही नीचे दी जा रही प्रक्रिया को फॉलो करें और पाएं वृक्ष वीर वृक्ष वीरांगना उपाधि के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्राणवायु अवार्ड जीतने का मौका अंकुर योजना अंतर्गत प्राणवायु पुरस्कार के लिए नीचे दिए जा रहे हैं निर्देशों का पालन कर आज ही वृक्षारोपण कर वायुदूत एप्लीकेशन पर अपलोड करें।

- प्रतिभागियों को वायुदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन करना होगा।
- प्रतिभागियों को योजना की अवधि में कम से कम एक पौधे का रोपण स्वयं के संसाधन से करना है तथा रोपित पौधे का फोटोग्राफ एप पर अपलोड करना होगा।
- रोपित पौधा किसी देशज वृक्ष की श्रेणी का होना चाहिए बहुवर्षीय झाड़ियाँ जैसे कनेर, गुड़हल इत्यादि की श्रेणी के पौधे मान्य नहीं होंगे।
- रोपित पौधे की देखभाल रोपण एवं पौधे की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करना होगी।
- पौधरोपण के 30 दिवस उपरांत प्रतिभागी को दोबारा उसी पौधे का नवीन फोटोग्राफ एप पर अपलोड करना होगा।
- पौधे के विकास हेतु प्रतिभागी को देखभाल एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
- यह योजना मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में ही प्रभावी होगी।

एमपी अंकुर योजना वायुदूत एप्प रजिस्ट्रेशन एवं उपयोग

उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल एप्प तैयार किया गया है जिसका नाम वायुदूत ऐप है इसे उपयोग करने की प्रक्रिया नीचे दी गई हैं।

- जब कोई भी प्रतियोगी इस एप्प को डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके नंबर पर एक ओटीपी आयेगा और उसके अनुसार पंजीकरण पूरा होगा।
- जो भी प्रतियोगी इसमें अपना पंजीकरण दर्ज करेंगे उन्हें प्रतियोगी बनने के लिए अपने वृक्षारोपण की फोटो 30 दिन तक अपलोड करनी होगी।
- इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी प्रक्रिया आप करेंगे उसका प्रमाण पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस एप्लीकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों को चयनित किया गया है जो वृक्षारोपण स्थलों का सत्यापन स्वयं जाकर करेंगे और मुख्यमंत्री तक एक लिखित रिपोर्ट भेजेंगे।

ऐसे होगा प्राणवायु पुरस्कार योजना के लिए चयन

कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से जिलेवार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पृथक पृथक कम से कम 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 प्रविष्टियों का random basis पर कलेक्टर द्वारा जनभियान परिषद के volunteers तथा NGC मास्टर ट्रेनर मे से नामांकित जिला स्तरीय verifiers के द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

- कम्प्यूटर आधारित लॉटरी के माध्यम से सभी प्रतिभागियों में से जिलेवार विजेताओं का चयन किया जायेगा।
- चयनित विजेताओं द्वारा लगाये गए पौधों का वास्तविक सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- विजेताओं को वृक्ष वीरें और वृक्ष वीरांगनाओं के रूप में जाना जाएगा।
- इन विजेताओं को मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा 'प्राणवायु अवार्ड' देकर सम्मानित किया जायेगा।

जिलेवार विजेताओं के चयन मापदंड निम्नानुसार होगें

- प्राणवायु अवार्ड के लिए वायुदूत एप्लीकेशन पर पंजीकृत मे से 50 प्रतिशत महिला व 50 प्रतिशत पुरुष प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा।
- समस्त प्रतिभागियों को योजना में सहभागिता के लिए सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- समस्त प्रतिभागी द्वितीय फोटो अपलोड करने के उपरांत वायुदूत एप पर सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
- प्रतिभागी समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से योजना में भाग ले सकते हैं।
- वृक्षारोपण हेतु घर के आँगन, शासकीय, अशासकीय भूमि, सामुदायिक स्थानों का उपयोग किया जा सकेगा।
- घर की छतों पर किये गए वृक्षारोपण अमान्य होंगे।
- यदि वृक्षारोपण शासकीय भूमि (राजस्व भूमि अथवा वन भूमि) या शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय संस्थानों के परिसरें या अशासकीय भूमि पर किया जा रहा है तो भी भूमि स्वामी से आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण हेतु प्रतिभागी को सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा जिससे रोपित पौधों की उत्तर्जीविता सुनिश्चित की जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत शासकीय सामुदायिक स्थल पर किये गये वृक्षारोपण से भविष्य में होने वाले
- लाभों के प्रथम हकदार समाज, राज्य शासन होंगे। यह शर्त निजी भूमि पर लागू नहीं होगी।
- सहमति प्राप्त स्थल पर किये गए वृक्षारोपण से प्रतिभागी को उक्त भूमि के स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होगा।
- प्रतिभागी केवल प्रतियोगिता के संभावित पुरस्कार के ही हकदार होंगे।

CECOEDECON - सतत विकास की यात्रा

❑ श्रीमती चारू जोशी

श्री शरद जोशी सिकोईडिकोन संगठन के संस्थापक थे। भारतीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज मंडल के बीच एक स्थापित आवाज, श्री जोशी मानव अधिकारों, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के साथ-साथ विकास संबंधी मुद्दों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य पेश करने के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय नागरिक समाज संगठनों और सामूहिकों का समर्थन और नेतृत्व करने के लिए 35 से भी अधिक वर्षों के लिए समर्पित थे। मूल रूप से एक जमीनी कार्यकर्ता, उनकी दृष्टि और कार्य सूक्ष्म (हाथ से जमीनी स्तर पर काम) से लेकर मैक्रो (वैश्विक स्तर की वकालत) तक उल्लेखनीय रहा है। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, श्री जोशी ने विकास क्षेत्र में कदम रखा। 80 के दशक की शुरुआत में जयपुर में बाढ़ राहत में मदद करते हुए वे जमीनी स्तर पर गरीबों की चिंताओं और संघर्षों से प्रभावित हुए, जहाँ से उन्होंने उनके पुनर्वास और सिकोईडिकोन की नींव रखने की दिशा में काम किया। श्री जोशी के समर्पित और मजबूत नेतृत्व में संगठन ने कई नवीन और अत्यधिक प्रभावी पहल की। समुदाय की अप्रयुक्त क्षमता को महसूस करते हुए और सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ विश्वास के कारण, श्री जोशी ने सिकोईडिकोन के कार्यों के सभी तत्वों में समुदाय आधारित संगठनों की अवधारणा को एकीकृत किया। श्री जोशी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी टीम के मजबूत प्रयासों के कारण ये समुदाय आधारित समूह अब अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी चिंताओं को उठाने की क्षमता रखते हैं। ये समुदाय आधारित समूह पूरे समुदाय के लिए मजबूत सहायक संरचना बन गए हैं और सीईसीओईडीसीओएन के काम में समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं।

श्री जोशी सर्वाधिक वंचित समुदायों और समूहों की आवाज को मंच प्रदान करने के हिमायती रहे हैं। और साथ ही उन्होंने भागीदार समुदायों के कल्याण को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवादों में सिकोईडिकोन की उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र वार्ता प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों और वंचितों के हित सुरक्षित रहें। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, श्री जोशी ने कई संगठनों और एजेंसियों के सदस्य और

बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी सेवा के माध्यम से स्वैच्छिक आंदोलन के विकास का लगातार समर्थन किया है। उन्होंने नियमित रूप से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा गठित कई समितियों के निमंत्रण पर अपने विशाल अनुभवों को साझा किया। वह हमेशा पेशेवर विकास के महत्व के बारे में मुखर रहे और उन्होंने कई पेशेवर संघों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया (एनएपीएसडब्ल्यूएआई) के निर्माण और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1982 में, श्री शरद जोशी ने सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सिकोईडिकोन) की स्थापना की। उन्होंने इस तरह के विकास को प्राप्त करने के लिए संगठन की स्थापना की, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत, प्रभाव में प्रभावी और वंचित लोगों की जरूरतों को संबोधित करता है। संगठन का उद्देश्य संगठन के सहयोगी समुदायों- अनुसूचित जातियों और जनजातियों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन और वंचित महिलाओं और बच्चों की क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में सक्षम हैं। वर्तमान में संगठन राजस्थान के 10 जिलों (जयपुर, टोंक, बारां, उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर और अजमेर) में जल संरक्षण, आजीविका सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय और मूलभूत अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एक बहु-विषयक टीम के साथ काम कर रहा है। संगठन का मानना है कि सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार, जल संरक्षण और पर्यावरण पर काम करते हुए, सिकोईडिकोन ने ग्राम स्तर पर समुदाय आधारित संगठनों का गठन किया, जिन्हें ग्राम विकास समितियाँ (Village Development Committees), युवा समूह, बाल पंचायत, महिला समूह कहा जाता है; और ब्लॉक स्तर पर किसान सेवा समिति (केएसएस) कहा जाता है।

पिछले 39 वर्षों से, सिकोईडिकोन मिट्टी और जल संरक्षण, जल संचयन, पारिस्थितिक पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि सहित प्रयासों के माध्यम से लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के लिए समर्थन कर रहा है। हस्तक्षेपों ने व्यापक स्थायी जल उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे संगठन को जमीनी स्तर पर पानी के संरक्षण के लिए एक समुदाय के नेतृत्व वाले आंदोलन का निर्माण करने में मदद मिली है। सिकोईडिकोन के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत की गई कार्रवाइयों ने जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और रखरखाव और प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से पानी के संरक्षण के लिए सामाजिक व्यवहार को बदलने में मदद की है। लचीलापन बढ़ाने के लिए, राजस्थान के 500 से अधिक गांवों में संगठन द्वारा शुष्क भूमि खेती और जल और मिट्टी संरक्षण के उपायों को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार का कार्य स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक शक्ति के साथ-साथ जमीनी स्तर पर पूरक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को एक साथ लाने और उपयोग करने में सफल रहा है। संगठन ने एनीकट, तालाबों, नाड़ियों, टंका, मिट्टी के बांध आदि सहित 250 से अधिक पारंपरिक जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया है, जो छोटे और सीमांत किसानों और बड़े पैमाने पर ग्रामीण समुदायों पर सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। इस क्षेत्र के प्रयासों से किसानों के लिए उन्नत कृषि पद्धतियों, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों, उन्नत बीज किस्मों या जैव-उर्वरकों के उपयोग आदि के संबंध में कई अवसर खुलते हैं। जल के क्षेत्र में, सिकोईडिकोन का प्राथमिक दृष्टिकोण समुदायों को जल प्रबंधन समाधान तैयार करने में

शामिल करना, अपेक्षित संसाधन प्रदान करके स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देना और समर्थन करना, प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना रहा है। सिकोईडिकोन ने लगभग 83 एनीकटों को विकसित और पुनर्जीवित किया। इन एनीकटों से प्रति वर्ष औसत अतिरिक्त जल संग्रहण क्षमता 170850 घन मीटर है, जिससे 100 से अधिक गांवों के लगभग 30000 परिवारों को लाभ हुआ है। समुदाय समर्थित जल प्रबंधन समाधान आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में प्रभावी साबित हुए हैं। आय में वृद्धि ने एसएचजी संघों को मजबूत करने में भी मदद की है जो अब नियमित रूप से दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं, साथ ही नियमित प्रशिक्षण के साथ-साथ क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। महिला संघों का विकास जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों का एक प्रमुख परिणाम था, जो महिलाओं की अधिक निर्णय लेने और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी है।

सिकोईडिकोन का दृष्टिकोण समुदायों को केंद्र में रखने के वर्षों के अनुभव और विज्ञान के साथ स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए मजबूत प्रक्रियाओं और प्रणालियों के मॉडल बनाने से उत्पन्न होता है जहां स्थानीय लोगों को न केवल लाभार्थी के रूप में माना जाता है बल्कि रचनात्मक अभिनेताओं के रूप में नीचे से ऊपर (bottom up) के विकास का नेतृत्व किया जाता है। पिछले 39 वर्षों में यह राजस्थान में एक परिपक्व, विकसित और जीवंत नागरिक समाज संगठन के रूप में विकसित हुआ है। आज संगठन को UN ECOSOC से भी मान्यता प्राप्त है।

नर्मदा समग्र के संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व पर्यावरर्ण मंत्री श्री अनिल माधव दवे जी, शरद जोशी जी के संगठनात्मक विकास के कार्यों से काफी प्रभावित रहे। अनिल जी की भी यही सोच थी कि स्थानीय स्तर पर संगठनों का क्षमतावर्धन करते हुए जल और पर्यावरण संरक्षण के काम ज्यादा प्रभावी तरीके से किए जा सकते है। सिकोईडिकोन के विकास कार्यों के व्यापक अनुभव को देखते हुए संस्था को वर्ष 2016 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विचार महाकुंभ के नॉलेज पार्टनर की जिम्मेदारी दी गई। इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की परिकल्पना श्री अनिल दवे जी द्वारा ही तैयार की गई थी। विचार महाकुंभ अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था जिसमें जलवायु परिवर्तन, स्त्री शक्ति, कृषि, कुटीर उद्योग व अध्यात्म जैसे विषयों पर गंभीर मंथन के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक संदेश जारी किया गया। □

(लेखक - जलवायु परिवर्तन शहरी प्रबंधन और विकास की विशेषज्ञ व इरास्मस विश्वविद्यालय से लिंग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के साथ शहरी प्रबंधन और विकास में मास्टर डिग्री, ससेक्स विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से अंतर्राष्ट्रीय वित्त में एक अतिरिक्त मास्टर डिग्री और विश्वविद्यालय से स्नातक, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, भवन और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय के अध्ययन में भी शामिल रही हैं।)

नर्मदा के गांधी

प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार व नर्मदा अनुरागी के रूप में जानते हैं। वास्तव में वेगड़ जी जैसे व्यक्तित्व को किसी परिधि मे बांधना उनके स्तर कम आंकने जैसा प्रज्ञा अपराध है। जैसे गांधीजी के बिना अहिंसा, श्री कृष्ण के बिना कर्मयोग, श्री राम के बिना मर्यादा रेखांकित नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नर्मदा के सौंदर्य को वेगड़ जी के बिना रेखांकित करना मुश्किल है।

❑ अशोक पाटीदार

श्री अमृतलाल वेगड़ जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी परिचय विशेष का मोहताज नही। वेगड़ जी से जो भी मिला, वह उन्हीं का मुरीद होकर रह गया। हमारी पीढ़ी को गांधीजी को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला लेकिन वेगड़ जी से मिलकर गांधीजी कैसे रहे होंगे यह अनुभव किया जा सकता है। मनुष्यों की भीड़ में एक ऐसी श्रेणी के मनुष्य जिनकी आत्मा पवित्रता के एक ऐसे स्तर पर है, जहां कथनी, करनी में कोई भेद नहीं होता। जिनकी जिव्हा कभी लड़खड़ाती नहीं, सीधे सपाट बोलती हैं। वही कहते एवं करते जो कहने व करने योग्य होता हैं। लोग उन्हें प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार व नर्मदा अनुरागी के रूप में जानते हैं। वास्तव में वेगड़ जी जैसे व्यक्तित्व को किसी परिधि में बांधना उनके स्तर कम आकने जैसा प्रज्ञा अपराध है। जैसे गांधीजी के बिना अहिंसा, श्री कृष्ण के बिना कर्मयोग, श्री राम के बिना मर्यादा रेखांकित नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नर्मदा के सौंदर्य को वेगड़ जी के बिना रेखांकित करना मुश्किल है। अमृतलाल वेगड़ जी का जन्म 03 अक्टूबर 1928 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था।

आपने गुरू रवीन्द्रनाथ टैगोर के शान्ति निकेतन से 1948 से 1953 के बीच कला की शिक्षा ली, फिर जबलपुर के एक कॉलेज में चित्रकला के अध्यापन का काम किया। वेगड़ जी पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव जी दवे द्वारा गठित नर्मदा समग्र न्यास के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक अध्यक्ष रहते हुऐ वे अनेकों बार नर्मदा समग्र न्यास के कार्यालय 'नदी के घर' पर आये। सौभाग्य से मुझे उनके साथ रहने का कुछ ज्यादा ही अवसर मिला। नर्मदा समग्र के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते सामान्य शिष्टाचार के कारण हमें जो व्यवस्था करनी होती थी वह तो हम करते ही थे, किंतु अनिल दवे जी भाई साहेब एवं वेगड़जी के संबंधों में एक अद्भुत केमिस्ट्री थी जिसका समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक बार वेगड़ जी को मैंने चाय दी, अनिल जी ने कहा यह क्या करते हो। उन्होंने चाय का कप मेरे हाथ

से लिया ओर वेगड़ जी को चाय प्लेट में देते हुए अपने हाथो में कप तब तक पकड़े रहे, जब तक वेगड़ जी ने चाय नहीं पीली। वैसा ही आतिथ्य वे उन्हें भोजन करवाते समय भी करते थे। वे एक दूसरे में ऐसे रचे बसे थे जेसे दो शरीर एक आत्मा। मेरे अपने नर्मदा मासिक प्रवास के दौरान जबलपुर वेगड़ जी के निवास पर जाना होता था तब नर्मदा समग्र के संस्थापक सचिव अनिल दवे जी भाई साहब का निर्देश रहता था कि उन्हें नर्मदा संरक्षण व संवर्धन के कार्यों से समय-समय पर अवगत करवाया जाए। नर्मदा संरक्षण नियमित गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने के बाद नर्मदा के प्रवाह में आए बदलाव को लेकर सहजता से पूछने पर वे कहते थे मेरे समय की नर्मदा अब कहा रही... मेरी पहली परिक्रमा (1977) के दौरान नर्मदा वैसी ही थी, जैसी वह सैकड़ों साल पहले थी। मगर खेद है अब वैसी नहीं है, अब तो वह स्थान स्थान पर झीलों में तब्दील हो गई। झील में प्रवाह कहा होता। वह तो ठहरा हुआ पानी भर है। और नदी का मूल तत्व है 'प्रवाह'...!

एक ही स्थान पर वो लिखते हैं प्रवाह नदी का प्रयोजन है। नदी अगर बहेगी नहीं तो वह नदी नहीं रहेगी। अपने अस्तित्व के लिए उसे बहना ही चाहिए। वेगड़जी ने अपनी पहली यात्रा सन 1977 में शुरू की थी जब वे कोई 50 साल के थे। 1977 में नर्मदा परिक्रमा करनी शुरू की, जो 2009 तक क्रमश खंडों में जारी रही। वास्तव में नर्मदा परकम्मा, परिक्रमा है, उसमें खंड परिक्रमा भी हैं और जिलहरी परिक्रमा भी यानि समुद्र संगम को लांघे बिना दुहरी परिक्रमा। कोई चार हज़ार किलोमीटर से अधिक वे इस नर्मदा के किनारे किनारे पैदल चलते रहे। कोई साथ मिले या ना मिले, अकेले ही, कहीं जगह मिली तो सो लिये, कहीं भोजन, कही सदावृत, सब कुछ बेहद मौन, चुपचाप और जब उस यात्रा से संस्मरण शब्द और रेखांकन सामने आए तो पाठकों के समक्ष नर्मदा का एक अद्भुत स्वरूप निखर कर सामने आया। इनमें उनके साथी-सहयोगी बदलते रहे। कभी दोस्त और परिचित साथ चले तो कभी अर्द्धांगिनी ने साथ दिया।

अपनी यात्रा के सम्पूर्ण वृतान्त को चार पुस्तकों में समेटा पहली पुस्तक 'सौन्दर्य की नदी नर्मदा' 1992 में आई थी। यह काफी लोकप्रिय हुई थी वैसे उन्होंने नर्मदा यात्रा पर तीन किताबें लिखीं, जिनमें 'सौंदर्य की नदी नर्मदा' काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा 'अमृतस्य नर्मदा', 'तीरे-तीरे नर्मदा' है। बाद में वर्ष 2015 में 'नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो' भी प्रकाशित हुई थी। वेगड़जी अपनी एक पुस्तक का प्रारम्भ करते हैं- ''कभी-कभी मैं अपने-आप से पूछता हूं, यह जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? और हर बार मेरा उत्तर होता, अगर मैं यात्रा न करता, तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिये बना हो, उसे वह काम करना ही चाहिए और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिये बना हूं।'' लेखक अपनी नर्मदा यात्रा में केवल लोक या नदी के बहाव का सौन्दर्य ही नहीं देखते, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर आदि के कारण लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव, विस्थापन जेसे मुद्दों को भी यथा स्थान छूते रहें।

नर्मदा उदगम से संगम तक के एक छोर का सफर 1,312 कि.मी है। यानी पूरे 2614 कि.मी. लम्बी परिक्रमा। विधान से करें तो तीन साल, तीन महीने और 13 दिन में परिक्रमा पूरी होती है। इतने लम्बे सफर में अनगिनत किस्से, कहानियां, दृश्य, एवं अनुभव को सहेजता यात्री अगर चित्रकार के साथ कथाकार भी हो तो यात्राओं में मिलें प्रसाद को कैसे अपने पास रख सकता है? मूल में लेखक एक चित्रकार हैं और उनके कोलाज-रेखाचित्रों में गूथे जाने पर अपना परिचय स्वयं देते है। लेखक की विशेषता यह है कि वह केवल नर्मदा पर बात नहीं करते, वह वहां उसके किनारे पली-बढ़ी उसकी संतति को कैसे स्पर्श करते हैं उसकी एक बानगी देखिए उन्होंने एक अन्य जनजातीय परंपरा का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण दिया है। जिसमें कहा गया है कि- ''कन्यादान लड़की का पिता करता है, दाता वह है। दाता की शोभा इसी में है कि वह खुद जाकर दान करे, किसी को माँगने के लिए उसके घर न आना पड़े। इसीलिए वह बेटी की बारात लेकर लड़के वालों के घर जाता था। यह ब्रह्मर्षि विवाह है। जिसमें लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है, यह राजर्षि विवाह है। लेकिन अब इसी का रिवाज है। ''वेगड़ जी के शब्दचित्र और रेखाचित्र में अदभुत संयोजन हैं। आपने न केवल उन अनुभवों को पुस्तकों में संजोया अपितु नर्मदा अंचल में फैली बेशुमार जैव विविधता से दुनिया को परिचिय कराया।

नर्मदा नदी के प्रति लेखक का विशेष अनुराग है। लेखक लिखते हैं कि ज्यों-ज्यों जीवन का सूर्यास्त निकट आता है; अधिकांश चीज़े छूटती जाती हैं और यात्री अंतिम यात्रा के लिए हल्का होता जाता है। आगे लिखते है- 'पहले आनंद की हर चीज़ बाहर थी- नदी, पहाड़, जंगल, तीर्थ, फूल, पक्षी अब सब कुछ अंदर है- टीवी के डिब्बे में! टीवी ने हमें घर घुसरा और निष्क्रिय बना दिया है। और बदले में आनन्द भी नहीं दिया। अमृतलाल वेगड़ जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने नर्मदा यात्रा के अनुभवों से अपने पाठकों को नदी से संवाद करना सिखा देते है। एक स्थान पर वेगड़ जी लिखते हैं- ''नर्मदा तट के छोटे-से-छोटे तृण और छोटे-से-छोटे कण न जाने कितने परव्राजकों, ऋषि-मुनियों और साधु-सन्तों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहां के वनों में अनगिनत ऋषियों के आलम रहे होंगे। वहां उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही। लेकिन अब..? हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु-पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है, धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है।'' वेगड़जी कहते हैं कि यह नर्मदा को समझने-समझाने की उनकी एक ईमानदार कोशिश है और वे कामना करते हैं कि सर्वस्व दूसरों पर लुटाती ऐसी ही कोई नदी हमारे सीनों में बह सके तो नष्ट होती हमारी सभ्यता-संस्कृति शायद बच सके। नगरों में सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति गांव और गरीबों में ही थोड़ी बहुत बची रह गई है। लोकजीवन के रंग-बिरंगे रेखांकनकार अमृतलाल जी वेगड़ ने नर्मदा तट पर बसे अपने प्रिय गृह नगर जबलपुर (मध्य प्रदेश) में 6 जुलाई 2018 की सुबह अपनी सार्थक ज़िंदगी की आखरी साँस ली। सार्थक इसलिये कि उनसे नर्मदा को अलग कर देखना मुश्किल है। □

(लेखक - कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व संभाग समन्वयक जन अभियान परिषद एवं पूर्व प्रबंधक, नर्मदा समग्र)

स्वर्णा की सुवर्ण आराधना

❑ डॉ. नारायण शैनॉय

हमारे जीवन में नदियों का पात्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम नदियों को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। जीव जल का स्रोत हैं, नदियाँ में सभी गावों और नगरों के नैर्मल्य का अंग मानी जाती हैं। नदियों के तट पर ही हमारे देश की प्राचीन नागरीकता और संस्कृति का विकास हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति में नदियों को अत्यन्त पुनीत भाव से देखा जाता है। हमारी धार्मिक गतिविधियों में हमेशा नदियो का स्मरण किया जाता है। पूजा-पाठ के अवसर पर जल से भरे कलशों में नदियों का नामोच्चारण के साथ मंत्रपूर्वक पुनीत आव्हान किया जाता है। समस्त जीवजंतुओं के आधारभूत पवित्र नदियों का संरक्षण करना आद्य कर्तव्य है। 'स्वर्णा' नामक नदी तो कर्नाटक राज्य के उडुपि जिले की, जीवनदी है। उडुपी जिले के कार्कल और उडुपि नगर के लोगों को पीने के लिए इसी नदी के जल का उपयोग किया जाता है। उडुपि जिले के, अलग-अलग स्थानों में इस नदी पर दो बांध बनाए गये हैं। गांवों में खेतीबारी के लिए भी स्वर्णा नदी के जल का उपयोग किया जाता है।

स्वर्णा नदी को बचाने और पुनश्चेतन करने के उद्देश से 02.10.2020 से 13.04.2021 तक उडुपी जिले में 'सुवर्ण आराधना' नाम का एक विशिष्ट जागृति आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। उडुपी जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश जी ने स्थानीय सिरा गणपति मंदिर के परिसर में वृक्षारोपण के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। करीब एक साल तक चलाये गये इस 'सुवर्ण आराधना' आंदोलन में जलानयन प्रदेश की हरियाली को बनाए रखने के उद्देश से निम्नलिखितत कार्यक्रम अर्थपूर्ण रूप से संपन्न हो गये -

- स्वर्णा नदी के तट पर नियमित रूप से स्वच्छता का कार्यक्रम सफल हुआ। करीब एक हजार से ज्यादा स्वयं सेवकों ने इसमें भाग लिया। तथा पच्चीस से ज्यादा संस्थाएँ इस कार्यक्रम से जुड़ी।
- उडुपी जिले के स्कूल के छात्रों के लिए भारतीय नदियों के बारे में कूट प्रश्न (क्विज) कार्यक्रम, परिसर स्नेही ईंट की तैयारी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब एक हजार छः सौ (1600) (विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
- उडुपि नगर के सभी 35 वार्डों में स्वच्छता का कार्य, घर-घर फल के पौधों का वितरण कार्य, नगर के आस पास में रहने वाले तालाबों का स्वच्छता कार्य आदि कार्यक्रम नियमित रूप से चले।
- स्थानीय मंदिरों में, नगर के कुछ घरों में स्वर्ण आरती कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें लोग श्रद्धा-भक्ति के साथ भाग लिया।
- स्वर्णा नदी के जलानयन प्रदेशों में नवग्रह वनों का और मीभ्यावाकी वनों का निर्माण हुआ करीब दस हजार पेड़-पौधों को लगाने का कार्यक्रम ठीक तरीके से संपन्न हुआ।
- फेसबुक, वाट्स एप्प और अन्य सामाजिक जल स्थानों के द्वारा स्वर्ण आराधना आंदोलन के बारे में संतों और प्रभावी व्यक्तियों के शुभ संदेश प्रसारित किए गये। यू-ट्यूब में नदियों के महत्व के बारे में वीडियों तैयार कर दर्शकों के सामने प्रदर्शित किए गये।

'परिसर गतिविधि उडपी' जिला ''संवेदना फेडरेशन उडुपी'', ''स्वच्छ भारत फ्रेंडस उडुपि'' इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से ''सुवर्ण आराधना'', आंदोलन के उपर्युक्त सभी कार्यक्रम उडुपि जिले के सभ्य नागरिकों के प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता से अर्थपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ❑

(लेखक - मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं; हाइड्रोलॉजी, भूजल, वर्षा जल संग्रहण में विशेषज्ञ है; विगत 28 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में)

नर्मदा के उद्गम से ही शुरू हो रही है नदी को खत्म करने की कोशिश

❑ निवेदिता खांडेकर

फोटो : अजय ताव

मध्य भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के लिए उद्गम स्थल से ही अस्तित्व का संकट शुरू होने लगा है। यह नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक के आस-पास के पहाड़ियों से निकलती है। इसके उद्गम में आस-पास के वनों की बड़ी भूमिका है। पर इन वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इंसानी विकास से जुड़ी गतिविधियों से नदी का कुदरती बहाव भी खत्म हो रहा है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से नर्मदा पर मंडरा रहे इन खतरों की जानकारी सामने आई है। जर्नल ऑफ किंग साउद यूनिवर्सिटी के मार्च 2021 अंक में प्रकाशित इस अध्ययन में इन खतरों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

पिछले चार दशक में नर्मदा नदी के कैचमेंट में जंगल कम हुए हैं। कृषि और दूसरी इंसानी जरूरतों के लिए पानी का दोहन बढ़ा है और इससे नदी की हालत खराब हुई है। अध्ययन का कहना है कि समृद्ध जैव-विविधता वाले इस क्षेत्र में 11.63 प्रतिशत डेंस मिक्स्ड फॉरेस्ट यानी सघन मिश्रित जंगल (डीएमएफ) है, वहीं 2.1 प्रतिशत हिस्सा साल के वृक्षों से भरा है। इस इलाके में वर्ष 1980 से 2018तक में खुले हिस्से का 7.52 प्रतिशत विस्तार देखा गया है। खुले हिस्से के विस्तार से तात्पर्य वनों की कटाई से है। इंसानी आबादी वाले क्षेत्र या इमारतों वाले इलाके इस दौरान करीब 4.18प्रतिशत बढ़ गए हैं। जमीन के प्रयोग में हुए बदलाव को समझने के मकसद से यह अध्ययन किया गया था।

- मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से ही नदी के अस्तित्व पर हमला शुरू हो गया है। नदी के उद्गम स्थल के अध्ययन में यह बात सामने आई है।
- उद्गम स्थल पर लोगों की बढ़ती आबादी, निर्माण और जंगल के ह्रास से नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। घास के मैदानों का ह्रास और प्रदूषण की वजह से नदी दम तोड़ने लगी है।
- अमरकंटक से नर्मदा के निकलते ही पहले तीन किलोमीटर में पांच चेक डैम और बैराज बनाए गए हैं जिससे नदी के कुदरती बहाव पर बुरा असर हुआ है।
- भारत सरकार और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने नदी के विकास पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बचाने से अधिक उसके आसपास कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है।

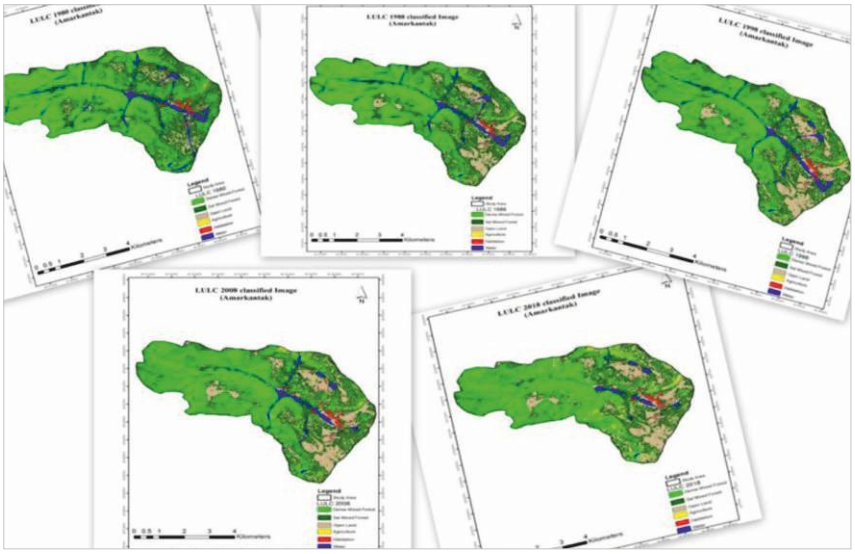

नर्मदा के उद्गम स्थल का इलाका अमरकंटक पिछले चार दशक में अपनी हरियासली खो रहा है। तस्वीर- अध्ययन से साभार

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का अमरकंटक शहर छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। नर्मदा का उद्गम दो पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और मैकल का मिलन स्थान भी है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला कुछ इस कदर स्थित है कि वहां वर्षा जल की भारी मात्रा नदी में एकत्रित होती है। यहां से तीन नदियां तीन दिशाओं में निकलती हैं- नर्मदा, जोहिला और सोन। अमरकंट में 1350 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर तक औसत वर्षा होती है जो कि यहां के घने जंगल, समृद्ध जैव-विविधता, साल के पेड़ और असंख्य जड़ी-बूटि के पौधों के लिए वरदान की तरह है। यूनेस्को की सूची में शामिल अचानकमार-अमरकण्टक जीवमण्डल रिज़र्व (एएबीआर) भी वर्षा-जल से ही गुलजार रहता है।

उद्गम स्थल पर एक मंदिर है और यहीं एक पत्थर के तालाब का भी निर्माण हुआ है। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। रास्ते में कई वेटलैंड्स, तालाब, छोटी जल धाराएं मिलती जाती है और नर्मदा विशाल होती जाती है। इन जल धाराओं में कपिल, वैतरणी इत्यादि शामिल हैं। नर्मदा नदी उद्गम स्थल से ही कई खतरों को झेल रही है। वर्ष 1970 तक अमरकंट इंसानी विकास की विभीषिका से लगभग अछूता था। वर्ष 1960 में यहां बॉक्साइट का खनन शुरु हुआ था जिससे इस स्थान पर चहल-पहल बढ़ी। वर्ष 2000 में इस खदान को बंद कर दिया गया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक शहर में मात्र 1,952 परिवार रहते है। यहां की कुल जनसंख्या 8,946 है। शहर में शांति का ऐसा आलम था कि कुछ 20 वर्ष पहले तक मात्र 35 से 40 दुकानें हुआ करती थी। वर्ष 2020 तक आते-आते उद्गम स्थल मंदिर के पास 100 दुकानें देखी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ का पक्का निर्माण भी हुआ है। शहर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से यहां आश्रमों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आश्रमों से निकलने वाला अपशिष्ट, नदी में बहाया जाता है। यहां के जंगल और जल-स्रोत एक साल में आने वाले करीब पांच लाख श्रद्धालुओं का भार झेल रहे हैं।

नर्मदा के लिए प्राण जितना महत्वपूर्ण जंगल हो रहा तबाह

इस अध्ययन में सामने आया है कि नर्मदा नदी को मजबूत करने वाली छोटी-छोटी जल धाराओं की धार कमजोर पड़ रही है। इसकी बड़ी वजह आसपास के जंगल का नष्ट होना है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रमुख तरुण कुमार ठाकुर कहते हैं कि खुली जमीन और इंसानों द्वारा किये जा रहे निर्माण से नदी घाटी के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। 'यहां जंगल समाप्त हो रहे हैं। अगर इसी तरह अवैज्ञानिकता के साथ इस इलाके की अवहेलना की जाती रही तो एक दिन सबकुछ खत्म हो जाएगा,' ठाकुर ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया। इस अध्ययन में सामने आया है कि नर्मदा के उद्गम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जंगल का दोहन भी किया जा रहा है जिसकी वजह से जंगल क्षीण हो रहे हैं।

उद्गम स्थल के मुख्य मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक नर्मदा नदी को पांच जल धाराओं से पानी मिलता है। इसमें इंद्र दमन तालाब, बट्टे कृष्ण तालाब, सूरजकुंड और मार्कंडेय तालाब इत्यादि शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले प्रशासन ने दो जल धाराओं को जोड़कर मंदिर के आसपास ही घेरकर रख लिया था, जिससे वहां आए लोगों को नहाने के लिए पानी दिया जा

अमरकंटक से निकलने
है जिससे इसके प्राकृति

सके। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के घरों से निकले कचरे (मल और गंदा पानी) को बिना सफाई किए ही नदी में जाने दिया जाता है। वर्ष 2019 में एक जल धारा सावित्री को गायित्री की धारा से मिलने से पहले साफ किया गया। नर्मदा समग्र संस्थान के सहयोग से इस जल धारा से गाद निकाला गया। नर्मदा मंदिर के एक संत नीलू महाराज का भी इसमें सहयोग लिया गया। 'हमने 300 मीटर लंबे क्षेत्र में 15 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा खुदाई की। खुदाई में कई ट्रक गाद निकला,' नर्मदा समग्र से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ता नीलेश कटारे कहते हैं। वह कहते हैं कि जंगल का तेजी से समाप्त होना भी नर्मदा पर बढ़ रहे संकट की एक बड़ी वजह है। 'इस स्थान पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। यह सही नहीं है,' वह कहते हैं।

तीन किलोमीटर में पांच अवरोध, कैसे बहेगी अविरल नर्मदा

उद्गम स्थल पर ही नर्मदा पर एक चेकडैम, अमरकंटक शहर में बने आश्रमों को पानी देने के लिए एक बांध सहित कई और रुकावट बनाए गए हैं। हालांकि, जंगल कम होने की वावजूद अ%छी बारिश और नदी के आसपास के इलाके की बनावट की वजह से नर्मदा में पानी की खास कमी नहीं हो रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अनूपपुर जिला पानी के मामले में सुरक्षित श्रेणी में आता है। बावजूद इसके आने वाले पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का खूब दोहन किया जा रहा है। जल आपूर्ति के लिए ही नदी की शुरुआत में ही कई चेक डैम बनाए गए हैं।

नदी कछार में निर्माण रोकने में असफल प्रशासन

वर्ष 2013 से लेकर 2017 तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) में नर्मदा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चार अलग-अलग आवेदन लगाए गए। मध्यप्रदेश सरकार ने एनजीटी को मार्च 2017 में कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नदी में 50 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता को परखता रहता है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अमरकंटक के दो स्थानों पर पानी की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, नदी से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण न करने

के बाद नर्मदा को कई निर्माणों को पार कर निकलना पड़ता
क बहाव पर असर होता है। तस्वीर- अध्ययन से साभार

उद्गम स्थल के मुख्य मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक नर्मदा नदी को पांच जल धाराओं से पानी मिलता है। इसमें इंद्र दमन तालाब, बट्टे कृष्ण तालाब, सूरजकुंड और मार्कंडेय तालाब शामिल हैं।

पुष्कर सरोवर झील में जमी गाद को वर्ष 2020 में पहली बार निकाला गया। यहां आकर नर्मदा एक संकरी धारा के रूप में नजर आती है। इन अवरोधों की वजह से नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ है। तस्वीर- निवेदिता खांडेकर

के एनजीटी के निर्देश को पालन कराने में प्रशासन नाकामयाब रहा है। च' तीर्थ और कपिलधारा के पास नदी के किनारे आश्रम बने हैं, और ऐसे ही कई निर्माण नदी के आसपास भी हुए हैं। एनजीटी में वर्ष 2016में वकील धर्मवीर शर्मा ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज करवाया था जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिसंबर 2020 में जिला अधिकारी को नोटिस दिया था। 'सरकार की बेरुखी की वजह से इस स्थान का प्राकृतिक स्वरूप खत्म हो रहा है और इसकी ऐतिहासिकता के साथ-साथ आध्यात्मिक महत्व भी खत्म हो रहा है,' शर्मा कहते हैं।

अमरकंटक नगर परिषद की सदस्य अंजना कटारे कहती हैं, 'यहां पांच बड़े आश्रमों का राजनीतिक लोगों से वास्ता है, इस वजह से नगर परिषद से उन्हें किसी अनुमति की जरूरत नहीं। वे ऊपर से ही आदेश ले आते हैं।'

कहीं 'सरकारी विकास' की चपेट में न आए नर्मदा

पर्यावरण की चिंताओं के बावजूद सरकार का ध्यान इस स्थान के 'विकास' की तरफ है। यह विकास पर्यावरण का विनाश कर ही संभव है। हालांकि, सरकार अपनी इस मंशा से इनकार करती है। सरकार ने वर्ष 2017 में अमरकंटक को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी इसी योजना का हिस्सा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद जोशी ने यहां 50 करोड़ की विकास की योजना शुरू की जिसके तहत इंद्र दमन तालाब का जीर्णोद्धार और कपिलधरा और सोनमुद्रा के बीच कांच का पुल निर्मित किया जाएगा।

अमरकंटक से खत्म हो रहा जंगल

अमरकंट के आसपास बसने वाले 15 गावों में बैगा, गोंड, उमरावन जनजातियां रहती हैं। ये लोग जंगल पर आश्रित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर आसपास के रेस्टोरेंट को उपलब्ध कराते हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इस काम में पेड़ की कटाई भी शामिल है।

शहर में आश्रम और मंदिर बनाने के लिए पेड़ों की बेतहासा कटाई हुई है। उदाहरण के लिए इस स्थान पर एक विशाल जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें पार्किंग और दुकानों के लिए कई पेड़ों को काटा गया है। इसी तरह कपिला नदी के मैदान में कब्जा कर खेती होने लगी है, जिससे नदी का दायरा कम होता जा रहा है। □

(लेखक - एसोसिएट एडिटर आईएएनएस, दिल्ली। वन, पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर लेखन करती है। यह लेख स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मोंगाबे इंडिया के लिए लिखा गया था।)

नर्मदा के उद्गम स्थल के समीप गावों में जनजातियां रहती हैं। रोजगार के अभाव में वे जंगल की लकड़ियां काटकर आसपास के पर्यटन स्थलों पर रेस्टोरेंट और आश्रम में इन लकड़ियों को बेचा जाता है। इससे अमरकंटक का जंगल खत्म हो रहा है। तस्वीर- निवेदिता खांडेकर

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित करने के उपरान्त चंबल की जैव विविधता को कायम रखने की असली चुनौती तो अब है

❑ डॉ. मनोज जैन

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2, 2020 को अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) घोषित कर दिया है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को शून्य से दो किलोमीटर के दायरे में ईको-सेंसेटिव जोन के रुप में घोषित किया है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र के कारण शापित यह चंबल अब गंभीर रुप से लुप्तप्रायः हो चुके घडियालों के लिए जीवन दायनी सिद्ध हो चुकी है। यही नहीं पतित-पावनी गंगा के भयकंर प्रदूषित जल से प्राण बचा कर भागी मीठे पानी की गैंगेटिक डाल्फिन को भी यहीं आश्रय मिला है। दुनिया के 75 प्रतिशत घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में है। 180 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का तथा मीठे पानी के कछुओं के अलावा कई जलीय जीवों का यह प्राकृतिक आवास है। मीठे पानी के कछुओं की नौ प्रजातियां यथा वांटागुर, वांटागुर डोंगोका, टैंटोरिया, निलसोनिया गैंजेटिक्स, हारडेला थुरगी, चित्रा इण्डिका, निलसोनिया हयूरम, लेसिमस पंटाटा, लेसिमस ऐंडरसनी पायी जाती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा था कि वह पर्यावरण की दृष्टि से बदहाल हो चुके क्षेत्रों को अपग्रेड और बहाल करने के लिए एक जोनल मास्टर प्लान बनाए। मंत्रालय ने क्षेत्र में मौजूदा जल निकायों और भूजल प्रबंधन के संरक्षण के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे। अब मध्यप्रदेश सरकार को मिट्टी और नमी संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अन्य पहलुओं के लिए एक उचित योजना तैयार करनी है। परन्तु मार्च महीने में मध्यप्रदेश में घटित राजनैतिक उथलपुथल के परिणामस्वरुप हुए सत्ता परिवर्तन तथा कोरोना संकट से उपजी त्रासदी के कारण अभी तक सब कुछ अधर में हैं, जिस पर तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

> "पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र के कारण शापित यह चंबल अब गंभीर रुप से लुप्तप्रायः हो चुके घडियालों के लिए जीवन दायनी सिद्ध हो चुकी है। यही नहीं पतित-पावनी गंगा के भयकंर प्रदूषित जल से प्राण बचा कर भागी मीठे पानी की गैंगेटिक डाल्फिन को भी यहीं आश्रय मिला है।

ईको-सेंसेटिव जोन के क्या मायने हैं

ईको-सेंसेटिव जोन (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र) एक संरक्षित क्षेत्र होता है। पर्यावरण की गंभीर छति के परिणाम स्वरुप प्रकृति को जो आघात लगते है उनसे बचाने का कार्य करने के कारण इसे ''सॉक ऐबजोर्बर'' कहा जाता है। ईको-सेंसेटिव जोन में कृषि क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों और अन्य खुले स्थानों को आवासीय या व्यवसायिक उद्देश्यों के क्षेत्रों में नहीं बदला

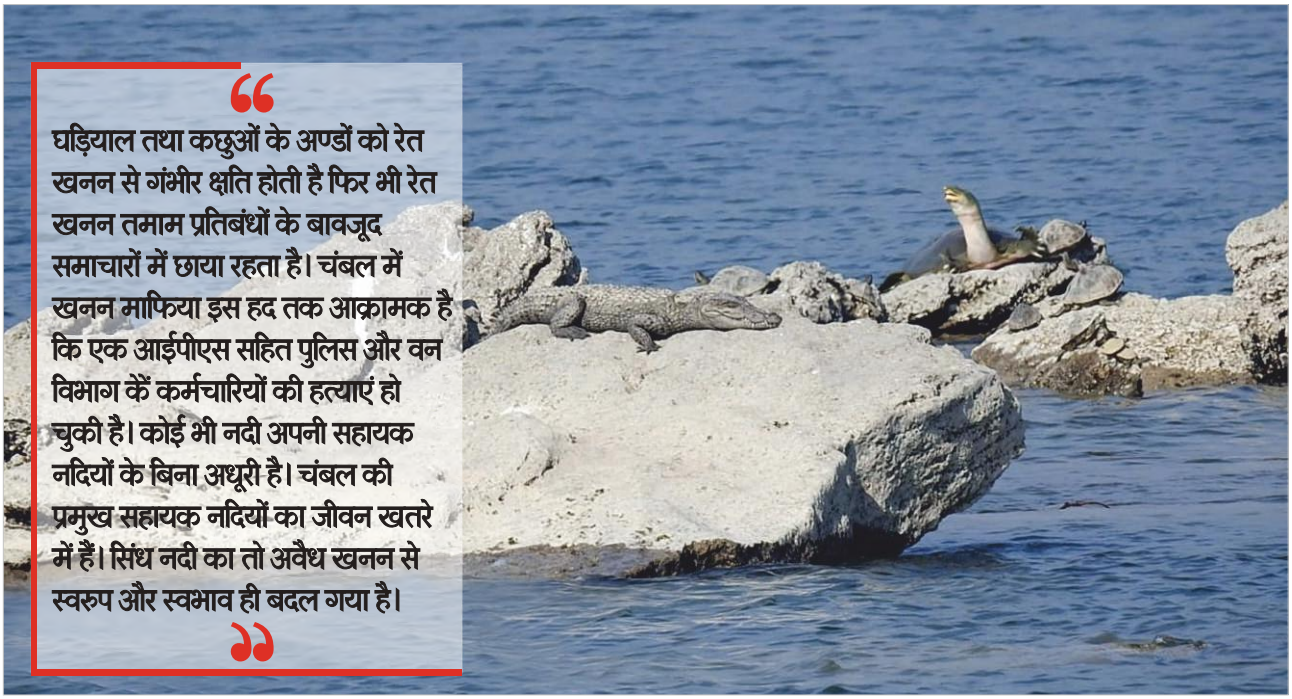

> घड़ियाल तथा कछुओं के अण्डों को रेत खनन से गंभीर क्षति होती है फिर भी रेत खनन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद समाचारों में छाया रहता है। चंबल में खनन माफिया इस हद तक आक्रामक है कि एक आईपीएस सहित पुलिस और वन विभाग कें कर्मचारियों की हत्याएं हो चुकी है। कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों के बिना अधूरी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों का जीवन खतरे में हैं। सिंध नदी का तो अवैध खनन से स्वरुप और स्वभाव ही बदल गया है।

जा सकेगा। जिससे दुर्लभ और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण कर इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। लुप्तप्रायः प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास के विनाश को रोका जा सके। यह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सं मण क्षेत्र के रुप में भी कार्य करते हैं। ईको-सेंसेटिव जोन से वन का विनाश तथा मानव-पशु संघर्ष कम होता है। इन क्षेत्रों का नियंत्रण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान की त्रिवेणी सीमा पर स्थित है। यह विंध्य रेंज से प्रारम्भ होकर इटावा जिले में बरेह नामक पर यमुना नदी पर समाप्त होता है। मध्यप्रदेश में यह भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में स्थित है जो 435 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित है।

ईको-सेंसेटिव जोन के मार्ग की चुनौतियाँ क्या है?

ईको-सेंसेटिव जोन की विडम्बना यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986में ''ईको-सेंसेटिव जोन'' शब्द का उल्लेख ही नहीं है। अधिनियम की धारा 3 (2) (अ) में कहा गया है कि केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है जिनमें किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाओं को कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 5 (1) के अलावा, केंद्र सरकार उद्योगों के स्थान को प्रतिबंधित कर सकती है तथा एक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित संचालन या प्रक्रियाओं को कर सकती है। उपरोक्त दो खंडों को सरकार द्वारा ईको-सेंसेटिव जोन या पारिस्थितिक रुप से नाजुक क्षेत्र घोषित करने के लिए आधार बनाया जाता है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को भारत सरकार ने अपने आदेश' 17-74/77-एफआरवाय (वाइल्ड लाइफ) दिनांक 30 सितम्बर 1978 के तहत घोषित कर दिया था। परन्तु तब से आज तक चंबल की जैव विविधता को गंभीर छति पहुंची है। 1975 के आसपास तक चंबल में शीश म की बहुतायाद हुआ करती थी परन्तु विभागीय अमले की मौजूदगी के बावजूद भी चंबल के बीहड मिट्टी के नंगे टीलों में बदल गये। मैनें स्वंय चंबल में किंग वल्चर के झुण्ड देखें है। पर ऊँचें पेडों के कट जाने से नेस्टिंग में आई कठिनाइयों से वह पलायन कर गए।

जैवविविधता की संकल्पना को दरकिनार करते हुए तमाम विशेषज्ञों की राय को ताक पर रखते हुए 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह के द्वारा पूरे क्षेत्र पर सुबबूल के बीजों का हवाई छिड़काव किया गया। परिणामस्वरुप बरगद, गूलर, पीपल, पलाश , बेर, करौंदा, करंज, शहतूत, फालसा, नीम, अर्जुन, बेल, लभेडा, आंवला तथा सेमल की विविधता वाला चंबल का अंचल विलायती बबूल से आच्छादित हो गया है। विलायती बबूल का कांटा बहुत तीक्ष्ण होता है जिससे यहाँ के बीहड से जानवरों का पलायन हो चुका है। गद्दी बाले जानवरों से क्षेत्र लगभग शून्य हो चुका है। और तो और नीलगाय और शाकाहारी जानवर भी बीहड में गांव के आसपास दिन में केवल छुपने के लिए जाते है तथा पौ फटते ही एंव सांझ ढलते ही इनका खेतों पर आक्रमण शुरु हो जाता है। चंबल के किनारे खेतों पर किसानों ने बिजली के नंगे तारों से फसलों की सुरक्षा का सरल मार्ग अपना रखा है। जो विभाग की पेट्रोलिंग के बावजूद भी जारी है। ऊदबिलाव की दुनिया में 13 प्रजातियां है उनमें तीन भारत में मिलती हैं। चंबल में कभी यह बहुतायाद में दिखते थे जो अब लुप्त प्रायः है। सीवेट तो अभी पिछले दशक तक मैंने स्वयं कई बार देखी थी पर अब इसके भी दर्शन दुर्लभ हो गए है। से ही, मोनिटर लिजार्ड भी शिकार की भेंट चढ़ चुकी है। अभी

इसी 3 मई को अटेर वनमण्डल के फूफ रेंज के बढपुरा में तेंदुआ मानव-पशु संघर्ष में मारा गया।

घड़ियाल तथा कछुओं के अण्डों को रेत खनन से गंभीर छति होती है फिर भी रेत खनन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिदिन के समाचारों में छाया रहता है। चंबल में खनन माफिया इस हद तक आक्रामक है कि बीते सालों में एक आईपीएस सहित पुलिस और वन विभाग कें कर्मचारियों की हत्याएं हो चुकी है। कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों के बिना अधूरी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों का जीवन खतरे में हैं। सिंध नदी का तो अवैध खनन से स्वरुप और स्वभाव ही बदल गया है। इसके अलावा म.प्र., उ.प्र. एवं राजस्थान के वन विभाग एंव सेन्चुरी के अधिकारियों में समन्वय का अभाव एक बडी चुनौती है। वर्षो से एक राज्य के अपराधी दूसरे राज्य में शरण पाते रहे है। उप्र की सीमा में ऊँटो के माध्यम से रेत की तस्करी निरंतर बनी ही रहती है। इससे जलीय जीवों के अण्डों को नुकसान पहुँचता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन बनने के बाबजूद भी तीनों राज्यों में एक जैसी राजनैतिक तथा प्रशासनिक इच्छशक्ति का न होना ही बडी चुनौती साबित होगा।

गाँधी सागर से कोटा तक चंबल पर बने बाँधों की श्रृंखला ने भी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको सिस्टम को छति पंहुचाई है। इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में इन बाँधों से छोडे गये अमर्यादित जल ने जलीय जीवों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास का नष्ट किया। इस साल प्रवासी पक्षी बहुत कम संख्या में देखे गये हैं। जो गम्भीर चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन बन जाने के बाबजूद एक बड़ी चुनौती स्थानीय राजनीति से मिलेगी, ग्वालियर और मुरैना के स्थानीय नेताओं से लेकर केन्द्रीय मंत्री तक चंबल के पानी को ग्वालियर और मुरैना पहुंचाने की कवायद में लगे ही हुए है। ईको-सेंसेटिव जोन में पेड़ों की कटाई, होटल और रिसोर्ट की स्थापना, प्राकृतिक पानी का व्यवसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि की प्रणाली में व्यापक परिर्वतन, भारी प्रोद्योगिकी, कीटनाशक आदि का प्रयोग, सड़कों का चौड़ीकरण विनियमित गतिविधियां है। पर तत्कालीन भिण्ड कलेक्टर और बाद में पर्यटन मंत्रालय में सचिव बन कर गए एक आईएएस निरंतर चंबल के इस ईको-सेंसेटिव जोन में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।

ईको-सेंसेटिव जोन में वाणिज्यिक खनन, मिलों, उद्योगों के कारण प्रदूषण जिसमें वायु, जल, मिट्टी, शोर शामिल है। प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यवसायिक उपयोग, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे जैसी पर्यटन गतिविधियाँ, निर्वहन अपषिष्टों या किसी भी ठोस अपषिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन प्रतिबंधित होता है। ईको-सेंसेटिव जोन की अधिसूचना के बावजूद भी जून में ही मुख्यमत्रीं शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वेबीनार पर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने चंबल एक्सप्रेस वे की फिर घोषणा की बल्कि साफ-साफकहा कि कि हमें केवल सड़क ही नहीं बनानी है अपितु सड़क के दौनों ओर बड़े उद्योग भी निर्मित करने है, जिसमें यह स्पष्ट ही नहीं है कि ईको-सेंसेटिव जोन के प्रावधानों के अनुसार 10 किलोमीटर के क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देने पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल भी बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क की भांति सिकुड़ तो नही जाएगा। यह ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे अभी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित होने के बाबजूद भी जूझना होगा।□

(लेखक - वन्य जीव छायाकार हैं और चम्बल की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं।)

पानी के लिए ही होगा तीसरा विश्वयुद्ध ऐसा हर कहीं सुनने को मिलता है

क्या हो सकते हैं इसके कारण आइए जानते हैं

❑ संजय सैलानी

पृथ्वी का लगभग 71 प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है, 1.6 प्रतिशत पानी ज़मीन के नीचे है और 0.001 प्रतिशत वाष्प और बादलों के रूप में है, पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97 प्रतिशत सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3 प्रतिशत पानी पीने योग्य है जिसमें से 2.4 प्रतिशत ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है केवल 0.6 प्रतिशत पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, और एक रोचक बात ये भी है कि ये मात्रा घटती बढ़ती नहीं है। सागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है और फिर सागरों में जा समाता है और ये चक्र चलता रहता है।

मध्यप्रदेश में 94689 वर्ग किमी वन क्षेत्र है जो कि देश के कुल वनों का 12.30 प्रतिशत है। ग्लेशियर से बहने वाली सदानीरा नदियों की तुलना में मध्यप्रदेश के वनों से जन्मी नदियों की उपयोगिता जरा भी कम नहीं है। मध्यप्रदेश में औसतन 54 इंच वर्षा होती है। पूरा मध्यप्रदेश नर्मदा नदी के तट पर विस्तार लिए हुए है। अमरकंटक से बहने वाली नदियों में सोन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो वनों से निकलती है। इसके अतिरिक्त बेतवा, चंबल, कूनो, सिंध, धसान, केन, देनवा, टोंस, रिहंद, तवा, क्षिप्रा, शक्कर आदि नदियां यहां प्रवाहमान है। मध्यप्रदेश का कृषि में, बिजली उत्पादन में, हीरा, कोयला जैसे खनिजों के दोहन में शीर्ष पर है। यहां देश में सबसे अधिक बाघ हैं, तेन्दुए, घड़ियाल, गिद्ध हैं। इकोपर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे चल रहा है मध्यप्रदेश। वनोपज के दोहन में भी अग्रणी है। सबसे ज़्यादा आदिवासी भी यहीं रहते हैं। यहां 9 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। इन तमाम ब्यौरों का अर्थ ये है कि वनों से जन्मी नदियों के कारण यहां की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र आदर्श स्थिति में रहा है यही कारण है कि मानव सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष नर्मदा घाटी में मिलते आए हैं। जंगल से निकलने वाली नदियों में पानी की सालभर उपलब्धता से न केवल भौगोलिक विविधता बढ़ी साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता भी उतनी ही विस्तृत हुई।

समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें जो अमृत था उसे बहुत से ऋषि और ज्ञानी लोग उस पानी को मानते हैं जो पीने योग्य है। नदियां जहां से जन्म लेती हैं वहीं से सभ्यता भी जन्म लेती है। प्रकृति अपने सबसे सृजनात्मक रूप में यहीं पर होती है।

नदियों के उद्गम वाले स्थान पर सबसे दुर्लभ वनस्पति और जीवजंतु पाए जाते हैं। नदियों के इर्द गिर्द सबसे सघन वन होते हैं। इन नदियों में प्रवाहित पानी सूर्य की रोशनी, जंगल की औषधियुक्त मिट्टी, स्वच्छ वायु से परिमार्जित होता है। यानी बिना मशीन के प्राकृतिक रूप से पानी का शुद्धिकरण होता है और साथ ही जंगली वनस्पतियों और मिट्टी से औषधीय गुण लिए होता है। ऐसे आदर्श स्थानों पर भोजन, पेयजल, शुद्ध हवा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के वजह से साल में अधिकतम धूप भी उपलब्ध रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ऐसी ही जगहों को अपनी साधना के लिए चुना जहां जीवित रहने हेतु आवश्यक द्रव्य सहज और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे। चूंकि मध्यप्रदेश में सैकड़ों नदियों का उद्गम है उसमें भी देश की सबसे प्राचीन नदियों में से एक नर्मदा नदी यहां से प्रवाहित होती है इसलिए देश की हर परंपरा के साधु, संत ऋषि, मुनि, जोगी, तपस्वी, बैरागी, तांत्रिक नर्मदा के तट पर रहे और अपनी साधना पूरी की। नर्मदा तो पुराणों में वर्णित वह नदी है जो मनुष्य के अहंकार (नर मद हर) को हर लेती है। मनुष्य का अहंकार ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। जो नदी सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दे वहां आध्यात्मिक चेतना वाले लोग उसका सान्निध्य प्राप्त करने जाएंगे ही। यही कारण है कि अगस्त्य ऋषि, मार्कण्डेय ऋषि, भृगु मुनि, कपिल मुनि, आदि शंकराचार्य से लेकर नानक, कबीर और नीम करौली बाबा तक नर्मदा तट पर अपनी साधना किए हैं। नर्मदा एकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा की परिक्रमा में हर तरह के सिद्ध लोग यात्रारत रहते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने से कोई न कोई संत मार्ग में टकरा ही जाते हैं ऐसी मान्यता है। आदि शंकराचार्य को भी उनके गुरु नर्मदा के किनारे यात्रा करते हुए ही मिले थे।

अगर पौराणिक और आध्यात्मिक कारणों से अलग भी देखें तो अगर कोई व्यक्ति नर्मदा के किनारे यात्रा करता है तो उसे अमरकंटक से खम्भात की खाड़ी तक हर तरह के जानवर, वनस्पति, कृषि के विभिन्न प्रकार, अलग तरह के पहाड़, अलग-अलग तरह की मिट्टी, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, गोंड, बैगा, कोरकू, भील भिलाला जैसे आदिवासी जीवन, भीमबेटका जैसी गुफाएं, कान्हा सतपुड़ा जैसे टाइगर रिज़र्व, लोक कला पर आधारित जीवन शैली सब कुछ देखने को मिलेगी। कोई व्यापारी बनना चाहे, किसान बनना चाहे या कलाकार, कोई योगी बनना चाहे या फिल्मकार, कोई वैज्ञानिक बनना चाहे या इतिहासकार नर्मदा में हर विधा के लिए पानी है रंग है और ऊर्जा है।

जंगल से जन्मी नदियों के पास ही जीवन का वैविध्य है, आरोग्य देने की क्षमता है, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की ऊर्जा है, संस्कृतियों को सहेजने हेतु आश्रय है, सबके

लिए आहार पैदा करने वाले तट हैं। बाघ से लेकर दीमक के अस्तित्व को ज़िंदा रखने का जीवित तंत्र है। हमारी स्मृतियों पर बाहर से जितने हमले हुए उतने ही हमारे स्वयं के भीतर की उदासीनता और अकर्मण्यता ने हमें अपने पानी से विमुख कर दिया है।

हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा जल है।हमने लगातार अपनी नदियों की संस्कृति की अवहेलना की है। हम मनुष्य होने की दौड़ में लगातार पिछड़ रहे है। हमारे आधुनिक विकास का मॉडल अनियोजित है और हमारा भविष्य अंधकारमय! जो सभ्यता अपनी नदी, अपने भीतर बहते उस नदी के पानी के प्रति कृतज्ञ नही है।उसकी आध्यात्मिक चेतना क्षीण हो चुकी है। ऐसे सभ्यताएं जो पानी को महज संसाधन मानती है उसका नष्ट होना तय है।जो समाज अपनी मां की हत्या में जाहिर तौर पर शामिल है उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे फलीभूत हो सकता है!

इसलिए अगला युद्ध देवताओं और दानवों के बीच नही अपितु पानी विहीन पत्थर हो चुकी सभ्यताओं के बीच होगा और यह पानी बनाम पत्थर हुई मनुष्यता के बीच होगा इस युद्ध का सुखांत तभी होगा जब ये संसार मनुष्य विहीन हो जाएगा और पानी फिर से अमरत्व को प्राप्त करेगा! □

(लेखक- पर्यावरणविद हैं।)

नर्मदा की सहायक नदियाँ

खुज नदी

नदी का नाम	-	खुज नदी
उद्गम	-	7 कोठी माण्डव, विकास खण्ड धरमपुरी, जिला धार
लम्बाई	-	40 किलोमीटर
संगम	-	नर्मदा, कुब्जा, संगम, धरमपुरी

धार जिले का प्रसिद्ध व प्राचीन दर्शनीय स्थान माण्डव जिसके एक कोने को सात कोट्ठी के नाम से जाना जाता है। किदवंती है कि यहां पर सातों कोठड़ियों में सोना भरा हुआ है। खुज नदी पर स्टापडेम बने हुए हैं। नदी में एक फुलका नदी व 17 नाले मिलते हैं। नदी पर साकल्दा तालाव बना है इससे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ा है, तथा पानी का सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है। नदी क्षेत्र में काली बावड़ी के समीप कुम्भारों द्वारा ईंट बनाने व भट्टे लगाने के लिए चार स्थानों पर अति' मण किया गया है। धरमपुरी में नदी बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है अतः इसे प्रदूषण मुक्त करवाना है। नदी पुनर्जीवन के लिए पुराने स्टापडेमों का गहरीकरण करवाना अति आवश्यक है। इसके साथ छोटे-छोटे नालों व नदी पर छोटे-छोटे स्टापडेम बनवाये जाना चाहिए इसके अलावा बोरी बंधान भी बनाने की आवश्यकता है।

नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये जन जागरण अंतर्गत प्रचार प्रसार व नुक्कड़ नाटक किये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को नदी का महत्व समझ में आ सके। खुज नदी की माण्डव सात कोट्ठी से धरमपुरी तक की लम्बाई 40 किलोमीटर है। खुज नदी का संगम स्थल धरमपुरी कुब्जा संगम है यह नर्मदा नदी में आकर मिलती है जिसका नाम कुब्जा संगम से जाना जाता है।□

खुज नदी वार्ड 1 खुजावा धरमपुरी - फोटो स्थान - हाथी दरवाजा के सामने खुज नदी पुल

जोधपुर झाल : जल भंडारण से आगरा की बुझेगी प्यास

❑ डॉ. अनुराग शर्मा

हम सभी कहते है जल ही जीवन है लेकिन हमारा मानना है की यह तो सत्य है ही साथ-साथ हमें यह भी मानना होगा की जल में भी जीवन है। इस समय विश्व, जल संकट से जूझ रहा है और हर जगह जल संरक्षण और संवर्धन के विषय पर चर्चा और कार्य दोनों हो रहे है। जलाधिकार फाउंडेशन आगरा की टीम भी अपने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रही है। जल स्त्रोतों की सुरक्षा और उनका संवर्धन उसमे सबसे प्रमुख है। जलाधिकार को लगता है और है भी की आज कही न कही वाटर मैनेजमेंट की भारी कमी है। कही पानी कम है कही बहुत ज्यादा, हमारे पास साधन है पर संकल्प का अभाव है। इसका एक उदाहरण आगरा में अंग्रेजो के ज़माने से बनी कृत्रिम झील 'जोधपुर झाल' का भी है। 1875 में आगरा के समीप बनी इस कृतिम झील पर अनेक वर्षो तक खेती होती रही।

कब्जे में थी जमीन

आगरा-फ़रह के बॉर्डर पर जोधपुर झाल की 55 हेक्टेयर जमीन पर कब्ज़ा था और खेती का कार्य चल रहा था सिचाई विभाग की जमीन पर आम जनता द्वारा कब्ज़ा किया जा चुका था। जलाधिकार की टीम ने प्रशासन के सहयोग से मुश्किल से जलाधिकार फाउंडेशन के प्रयासों से मुक्त कराई। सिंचाई विभाग की भूमि पर झील का स्वरुप बनाने का प्रयास शुरू हुआ, जलाधिकार फाउंडेशन 2016 से इस झाल को लेकर संघर्ष शुरू किया था।

चुनौती

जमीन को मुक्त करने के बाद अब जमीन के चारो और बंदा बनाने की बात तय हुई जिससे पुनः कब्ज़ा न हो सकें और एक सीमा तय हो जाए। प्रसाशन के सहयोग से और जेसीबी मशीन से 1100 मीटर लम्बा और 2.5 मीटर चौड़ी (मेढ) बनाने का कार्य आरम्भ हुआ। जलाधिकार के अवधेश जी, अनुराग शर्मा जी, राजीव जी एवं अन्य कार्यकर्ता प्रतिदिन जाते और कार्य संपन्न कराते थे। कई बार कार्य बाधित भी हुआ पर अंत में मेढ़ बनकर तैयार हुई।

मेढ़ बनवाने के बाद जलाधिकार फाउंडेशन आगरा की टीम ने उतरप्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया और लखनऊ में उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मुलाक़ात कर इस कृतिम झील जोधपुर झाल का नाम पंडित दीनदयाल सरोवर करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद इस पर कार्य और आगे बढ़ा और पानी भरा जाने लगा।

ओखला बैराज पर स्थित हैड रैग्यूलेटर से निकलने वाली अगरा नहर का सौ वे मील पर जोधपुर झाल पर टर्मिनल है। समय समय पर इसी नहर से झील में पानी भरा जाने लगा। इस स्थान पर नहर से आगरा राजवाह, टर्मिनल राजवाह और सिकन्दरा राजवाह में विभक्त हो जाती है। यही सिंचाई विभाग की लगभग 55 हैक्टेयर जमीन पर नये जलाशय बनाये जाने की योजना जलाधिकार फाउंडेशन आगरा द्वरा सिंचाई विभाग के सहयोग से प्रस्तावित कर दी गयी है। यह स्थान आगरा जनपद के अछनेरा विकास खंड मे है जिसे कि थम एस्केप से होकर सूर सरोवर को नहर का पानी दिया जाता है, उसी से होकर जलाशय का पानी भी यमुना नदी के माध्यम से आगरा के जलकलों के इंटेक वैलों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। जलाशय पर बांध बनाये जाने के लिये होने वाले अर्थवर्क के लिये आवश्यक मिट्टी 55 हैक्टेयर जमीन के एक टीले नुमा उठान लिये भाग में ही मौजूद है। जलाधिकार के प्रयासों से बांध बन भी गया लेकिन अभी अन्य कार्य होना बाकी है। यह स्थान पक्षियों के लिए भी अच्छा है। भरतपुर सेंचुरी निकट होने के कारण दूर देशों से पक्षी भी यहाँ आ जाते है।

क्यों जरूरी है जोधपुर झाल

जोधपुर झाल की उपयोगिता केवल आगरा की पेयजल जरूरत के अतिरिक्त स्त्रोत (सप्लीमेंट्री रिसोर्स) के रूप में ही नहीं आपितु नहरो के रोस्टर को रैग्यूलेट करने के लिये भी

है। वैसे तो यह जलाशय अपनी भौतिक स्थिति के कारण स्वतः ही आगरा की टर्मिनल रावाहा, कीठम एस्केपण, आगरा रजवाह, सिकन्दरा रजवाहाक चोरा, पगेरी राजवाहों के हैड पर होगा किन्तु इसके बावजूद जरूरत और जल उपलब्धता की सुनिश्चित स्थिति के लिये साइफन सिस्टम या डाल योजनाओं की तर्ज पर पानी की पम्पिंग का इंतजाम किया जा सकता है। जोधपुर झाल के पानी को सूर सरोवर तक बिना किसी नये चैनल को बनाये मौजूदा एस्केप के चैनल तक पहुंचाया जा सकता है। इस पानी के पहुंचने से बढे जल स्तर को सूर सरोवर से अक्टूबर-अप्रैल तक वन विभाग के द्वारा अपेक्षित किये गये स्तर पर सूर सरोवर के डिस्चार्ज पाइंट पर लगे सैल्यूझस गेट से यमुना नदी में डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस डिस्चार्ज पानी के यमुना में पहुंचने से पूर्व भी सूर सरोवर की लोअर लेक में रोके

पहली कृत्रिम झील की खुदाई शुरू

जल ही जीवन है लेकिन हमारा मानना है की यह तो सत्य है ही साथ-साथ हमें यह भी मानना होगा की जल में भी जीवन है। कही पानी कम है कही बहुत ज्यादा, हमारे पास साधन है पर संकल्प का अभाव है इसका एक उदहारण आगरा में अंग्रेजो के ज़माने से बनी कृतिम झील जोधपुर झाल का भी है 1875 से आगरा के समीप बनी इस कृतिम झील पर अनेक वर्षों तक खेती होती रही।

जाने की व्यवस्थाएं संभव होना प्रायः तय है। गंगाजल आने के बाद भी आगरा के लिये रॉ वाटर की जरूरत लगातार बनी रहेगी इस रॉ वाटर की आपूर्ति जोधपुर झाल के द्वारा संभव है।

जोधपुर झाल आगरा की जरूरत है संभावनाओं को दृष्टीगत निरीक्षण और योजनाओं का बनाया जाना सरकारी विभागों के लिये एक सामान्य प्रक्रिया है किन्तु आगरा के गिरते भूजल स्तर और यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बढती जा रही आबादी के बाद तो नदी और भूमिगत दोनों ही जलस्त्रोतों पर दबाव कही अधिक हो जाना है। इस लिये पर्यावरण और जलसंरक्षण की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप जोधपुर झाल को खास महत्व दिया जाना और अधिक अपेक्षित है। ☐

(लेखक - अध्यक्ष,
जलाधिकार फाउंडेशन आगरा)

वार्षिक सदस्यता प्रपत्र

मैं ..... एक वर्ष के लिए नर्मदा समग्र त्रैमासिक पत्रिका की सदस्यता लेना चाहता/चाहती हूँ।

4 अंक - वार्षिक शुल्क 100 रूपये, (पोस्टल शुल्क सम्मिलित)

नाम : _____ **लिंग :** _____

कार्य : व्यवसाय ☐ कृषि ☐ नौकरी ☐ विद्यार्थी ☐ संगठन ☐

संस्था : _____ **दायित्व/पद :** _____

फोन : _____ **मोबाइल :** _____ **ई-मेल :** _____

पता : _____

जिला : _____ **पिन कोड :** _____ **राज्य :** _____

भुगतान विवरण : चेक/डिमांड ड्राफ्ट नं. : _____ **दिनांक :** _____ **रूपये :** _____

अदाकर्ता बैंक : _____ **शाखा :** _____

खाते की जानकारी (ऑन लाईन भुगतान हेतु)

Narmada Samagra
State Bank of India
Shivaji Nagar Branch, Bhopal, M.P.
Ac no. 30304495111
IFSC: SBIN0005798

दिनांक : _____ हस्ताक्षर : _____

"नदी का घर"
सीनियर एमआईजी -2, अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462016
दूरभाष + 91-755-2460754 ई-मेल : narmada.media@gmail.com

खेती को कैमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति की लैब से जोड़ने की जरूरत - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को गुजरात के आणंद से देश के किसानों से जैविक खेती की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के गुर बताए। जिसमें किसानों को जैविक खेती से अवगत कराया गया। वैज्ञानिकों के माध्यम से भी जैविक खेती के उपाय, फायदे बताए गए। देशभर में भी इस कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को रासायनिक तत्वों के उपयोग से बढ़ती बीमारियों और आने वाली पीढ़ी को होने वाली परेशानी के बारे में जानकारी दी। साथ ही पैस्टिसाइड के उपयोग से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती के फायदे बताए।

प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिया गये संबोधन के मुख्य अंशः

मैं सभी किसान भाई-बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य देवव्रत जी का भी हदृय से अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वयं तो किसान नहीं हूँ, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था, कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका यह मार्गदर्शन और मैं जानबूझ करके आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था। क्योंकि मुझे मालूम था, कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं है। हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेगें, कभी भी भूलेंगे नहीं।

ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव, पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग-अलग आयाम हों, फूड प्रोसेसिंग हो, नैचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हज़ारों करोड़ रुपए के समझौते

उसकी भी चर्चा हुई, उसकी भी प्रगृति हुई हैं। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नॉलॉजी और नैचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैंफिर एक बार गुजरात के गवर्नर, आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को, नैचुरल फार्मिंग के बारे में इतनासरल शब्दों में स्वंअनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है।

आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का और उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सबने बहुत बारीकी से देखा है। अब आज़ादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है,वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाज़ार तक, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक, अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है।खेती के साथ-साथ पशुपालन, मधुमखी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल्स जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद काविकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सबके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दोचार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइज़र ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगाऔर अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से दुनिया के देशों से अरबों- खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है।

> “हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती-किसानी के इर्द-गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परम्पराएँ पोषित हुई हैं, पर्व-त्योहार बने हैं। जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली-फूली है, तो कृषि को लेकर, हमारा ज्ञान-विज्ञान कितना समृद्ध रहा होगा?”

गुजराती में एक कहावत है, हर घर में बोली जाती है पानी आवे ते पहेला पाल बांधे। पानी पहला बांध बांधो, यह हमारे यहां हर कोई कहता है... इसका तात्पर्य ये कि इलाज से परहेज़ बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाएं, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को कैमिस्ट्री की लैबसे निकाल कर नेचर यानि प्रकृति की प्रयोगशालासे जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है, इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है। हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है। और जैसा उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त करके भी यूट्यूब पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूढ़ेंगें उनके भाषण भी मिल जाएंगे।जो ताकत खाद में, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं, जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़-सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली ज़मीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं-धान-दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी, कम लागत, ज्यादा मुनाफा।यही तो प्राकृतिक खेती है।

आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही 'back to basic' की ओर बढ़ रही है। इस Back to basic का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना! इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती-किसानी के इर्द-गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परम्पराएँ पोषित हुई हैं, पर्व-त्योहार बने हैं। यहाँ देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं। आप मुझे बताइये, आपके इलाके का खान-पान, रहन-सहन, त्योहार-परम्पराएँ कुछ भी ऐसा है जिस पर हमारी खेती का, फसलों का प्रभाव न हो? जब हमारी सभ्यता किसानी के साथ इतना फली-फूली है, तो कृषि को लेकर, हमारा ज्ञान-विज्ञान कितना समृद्ध रहा होगा? कितना वैज्ञानिक रहा होगा? इसीलिए भाइयों

बहनों, आज जब दुनिया organic की बात करती है, नैचुरल की बात करती है, आज जब बैक टु बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं।

यहाँ पर कृषि से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्थित हैं जिन्होंने इस विषय पर व्यापक शोध किया है। आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक, कृषि-पाराशर और काश्यपीय कृषि सूक्त जैसे प्राचीन ग्रन्थों तक, और दक्षिण में तमिलनाडू के संत तिरुवल्लुवर जी से लेकर उत्तर में कृषक कवि घाघ तक, हमारी कृषि पर कितनी बारीकियों से शोध हुआ है। जैसे एक श्लोक है-

गोहितः क्षेत्रगामी च, कालज्ञो बीज-तत्परः।
वितन्द्रः सर्व शस्याढ्यः, कृषको न अवसीदति॥

अर्थात,

जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम-समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो, और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। ये एक श्लोक नैचुरल फ़ार्मिंग का सूत्र भी है, और नैचुरल फ़ार्मिंग की ताकत भी बताता है। इसमें जितने भी संसाधनों का जिक्र है, सारे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसी तरह, कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं, कब कौन सी फसल में पानी लगाएँ, कैसे पानी बचाएं, इसके कितने ही सूत्र दिये गए हैं। एक और बड़ा प्रचलित श्लोक है-

नैरुत्यार्थं हि धान्यानां जलं भाद्रे विमोचयेत
मूल मात्रन्तु संस्थाप्य कार्य्ये 'जज-मोक्षणम्'

यानी, फसल को बीमारी से बचाकर पुष्ट करने के लिए भादौ के महीने में पानी को निकाल देना चाहिए।केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए। इसी तरह कवि घाघ ने भी लिखा है-

गेहूं बाहें, चना दलाये।
धान गाहें, मक्का निराये।
ऊख कसाये।

यानी, खूब बांह करने से गेहूं, खोंटने से चना, बार-बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गन्ना बोने से उसकी फसल अच्छी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब-करीब दो हजार वर्ष पूर्व, तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर जी ने भी खेती से जुड़े कितने ही सूत्र दिये थे। उन्होंने कहा था-

तोड़ि-पुड्डी कछ्चा उणक्किन,
पिड़िथेरुवुम वेंडाद् सालप पडुम

अर्थात, If the land is dried, so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure.

साथियों,

कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की ज़रूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी ज़रूरत है। इस दिशा में हमें नए सिरे से शोध करने होंगे, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में ढालना होगा। इस दिशा में हमारे ICAR जैसे संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और theories तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस में बदलना होगा। Lab to land यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नैचुरल फार्मिंग को प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेगें।

नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी पड़ेगा जो खेती के तौर-तरीकों में आ गई हैं। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को और यह बात समझने जैसी है जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है, तो वो ईंट का रूप ले लेती है।और ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारे यहां परंपरा सी पड़ गई है।पता है कि मिट्टी जलती है तो ईट बन जाती है फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह, एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी नहीं होगी। जबकि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्री य सम्मेनलन को संबोधित करते हुए।

फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली, आगे बढ़ी। क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नालजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है! अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं।

नैचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा, वो हैं हमारे देश के 80 प्रतिशत छोटे किसान। वो छोटे किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च, केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी।

भाइयों और बहनों,

प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जहां शोषण होगा, वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे, कि मिट्टी को अलटना-पटलना भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधारा आ रहा है। हाल के बरसों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्ट-अप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है।

भाइयों और बहनों,

जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्साहवर्धक हैं। गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयास शुरु कर दिए थे। आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके

"21वीं सदी में नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइये, आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें।"

सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेज़ी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से, ये आग्रह करुंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आएं। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव ज़रूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, ये प्रयास हमसबकर सकते हैं।और मैं किसान भाईयों को भी कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपकी अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर ही प्रयोग करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो। चलिए उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, एक चौथाई खेत ले लो, एक हिस्सा तयकरो उसमें यह प्रयोग करो। अगर फायदा दिखता है तो फिर थोड़ा विस्तार बढ़ाओं। एक दो साल में आप फिर धीरे- धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे। दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में, इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जमकर निवेश का है। इसके लिए देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का बाज़ार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है।

इस अमृतकाल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चैंज समिट में मैंने दुनिया से Life style for environment यानि LIFE को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइये, आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएँ। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तब ही बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले, हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन, गोबर-धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी, हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जनांदोलन बनाएंगे, इसी विश्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का गुजरात के मुख्यमंत्री जी का उनकी पूरी टीम का इस initiative के लिए पूरे गुजरात में इसको जन आंदोलन का रुप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद ! □

❑ मारुती माने

सुभाष पालेकर कृषि (SPNF) भारत सरकार का आत्मनिर्भर किसा

हमारे किसान बीज बोने से फसल काटने तक का आर्थिक रूप से असहाय होते जा रहे हैं। छोटा हो या बड़ा किसान, इसके आय व्यय का कोई तालमेल नहीं अपितु उसे सरकारी सहायता, बैंक, सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेकर ही सभी कृषि कार्य करने पड़ते है। अपनी स्वयं की कोई अर्थव्यवस्था नहीं, फिर भी किसानी कार्य करने, अन्न-धान्य उत्पादन के इसी कुशलता को ही जीरो बजट कृषि कहेंगे अब हम इस व्यवस्था के बारे में जानेंगे।

"थामे ग्राम संस्कृति की डोर - चले पुनः प्रकृति की ओर"

साथियों मध्यप्रदेश की धरा पर मां अहिल्या की नगरी का कृषि इतिहास रहा है अब जीरो बजट खेती के अवधारणा से पुनः कृषि इतिहास का शंखनाद 2016 में हुआ था सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग शून्य बजट खेती। किसानों के बीच में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो इस खेती पद्धति को हमारे किसान अच्छी तरह से समझे और मध्यप्रदेश में अनाज, दलहन, तिलहन, फल सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर कर सके। इस पद्धति का मूल मंत्र - मुख्य फसल का खर्चा अंतरवर्तीय फसल से लेकर मुख्य फसल का खर्च पूर्ण रूप से मुक्त कराना होता है (अपवाद कुछ फसलों में यह संभव नहीं है, जिस फसल में पानी भरा जाता है वह)। अनिल माधव दवे जी अभ्यासु पर्यावरणविद, प्रखर वक्ता संवेदनशील राजनीतिज्ञ रहे हैं। मध्यप्रदेश में उन्हें थिंक टैंक कहा जाता था।

जहां तक प्राकृतिक खेती का विषय है अपने आप को भाई साहब विद्यार्थी के रूप में देखते थे। उन्होंने इस विषय को हरिद्वार में पालेकर जी के पांच दिवसीय शिविर में उपस्थित रहकर समझा फिर पालेकर जी की कार्यशाला का 2 मार्च से 6 मार्च 2016 तक आयोजन इंदौर में हुआ इस आयोजन में 700 किसानों का प्रशिक्षण का नियोजन था पर भारत वर्ष के 14 राज्यों से 1800 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। हम आयोजनकर्ता घबरा गए थे की इतनी व्यवस्था कैसे की जाएगी परंतु भाई साहब के कुशल नेतृत्व, स्थानीय नागरिक, ग्रामीण कृषक बंधु, इंदौर प्रशासन, मध्यप्रदेश कृषि कल्याण विभाग के सहयोग से यह आयोजन यादगार बना।

शुरुआत के दिन बारिश से प्रभावित हुआ परंतु पालेकर जी की वाणी से इंदौर की धरा पर किसान के इस जन आंदोलन का शंखनाद होना था बरसते पानी में भी सभी किसान बंधु एक घंटा वरुण देव का आशीर्वाद मानकर पंडाल में प्रशिक्षण लेते रहे यह बहुत ही विलक्षण अनुभव था। बहुत ध्यान से पांच दिनों तक उम्र के 16 साल के युवा से 70 से 80 साल के किसान बंधु ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंतिम दिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का संकल्प सहयोग का आश्वासन माननीय कृषि सचिव श्री राजेश राजोरा जी ने दिया।

माननीय भाई साहब अनिल जी ने सभी को मार्गदर्शन संकल्प दिला दिया अपने उद्‌बोधन में उनके शैली में परिभाषित किया उदाहरण में महर्षि पतंजलि का योगसूत्र का मूल मंत्र अथः योग का मतलब समझाया सब कर लिया, भाई साहब के शब्द थे- ''सब देख लिया, सब करने समझने के बाद समझ में आया कि इसमें रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है तब पतंजली जी कहते हैं 'अब योग'। मेरे विचार में भारतीय कृषि में 30 - 40 साल में अमूल्य बदल हुआ है, सब कर लिया रासायनिक देखलिया, जैविक देख लिया अब मैं बोल रहा हूं 'अथः शून्य बजट खेती'। यह सुभाष

जीरो बजट जन आंदोलन बना न योजना, कृषितिर्थ ग्राम का सपना

पालेकर कृषितंत्र सभी ने समझा, लिखा अब इस को क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है थोड़ी जगह पर करें, कोई साथ चले तो भी अन्यथा अकेले चलना पड़े तो भी इसे कीजिए यह ज्ञान मनोरंजन ना बने। यह ज्ञान प्रबोधन बने। यह व्यापार का अपनी जेब भरने का साधन ना बने। किसानों की समृद्धि का विकास का पर्याय बने। इसी गुरु मंत्र पर चलने का सभी सहयोगी, नर्मदा समग्र, भारतीय किसान संघ, ग्राम भारती, जन अभियान परिषद, कामधेनु गौशाला, भा.दे.न्यास, नोबल पर्सन हरिधरा कृषक सेवा समिति, भा.भू. न्यास, उत्सवचंद पोरवाल सेवा संस्थान और किसानों बंधुओं को संकल्प (प्रतिज्ञा) दिलाई।

स्वयं शिवनेरी पर इसका प्रयोग चालू किया था। मुझे याद है होली के तीन दिवसीय अवकाश में भाई साहब ने परिवार के साथ मुझे वहां आमंत्रित किया था। रात 9:00 बजे से सुबह 2:00 बजे तक अपने सहयोगियों के साथ मेरे इस विषय के प्रयोग अनुभव और कार्यप्रणाली को समझा। अंत में शायद उन्हें आभास हुआ होगा, किसानों के प्रति दायित्व किसी को प्रतिज्ञा पूर्वक सौपना था, मैं भाग्यशाली हूं, उनका सपना उन्होंने गुरु मंत्र देकर कहां गंभीरता पूर्वक समझो कृषि- कृषक विषय को व्यापार, स्वार्थ का साधन नहीं बनना चाहिए, साथ मिले या ना मिले अकेला चल पड़े तो भी छोड़ूंगा नही का संकल्प दिलाया। सुबह उठकर शिवनेरी पर मां नर्मदा के पावन तट पर मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी, दोनों बेटे सचिन स्वप्निल को साथ बैठाकर निस्वार्थ भाव से कृषि और कृषक की सेवा करने मुझे समर्पित करने का आदेश दिया। तब से मैं और यह दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने लगा हूं।

अगला पड़ाव सिंहस्थ 2016 में अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में विचार मंथन में भाई साहब ने स्वयं इस विषय को विचारवंताओं के बीच रखा। सार्वभौम अमृत संदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने इसे पटल पर लिया और 46वे बिंदु में शून्य बजट खेती अवधारणा को जगह दी इसे पूर्ण रूप से प्रचारित प्रसारित करने का संदेश दिया।

अगली कड़ी 2017 में भाई साहब

मेरा गांव मेरी पहचान - घर बाड़ा खेत खलिहान भूजल, भूस्थल, सौर ऊर्जा नभ वायु पर्यावरण वन, वृक्ष, हरियाली गोमय खुशहाल जीवन ग्राम देवता, स्थान देवता, गणगौरगोत्र पितृ पूजन संस्कृति, परंपरा, श्रद्धा विश्वास का सृजन स्वस्थ हो मानव जीवन प्राकृतिक कृषि का संगोपन पदम श्री सुभाष पालेकर कृषि (जीरो बजट खेती) तंत्र माननीय पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का शून्य बजट कृषि मंत्र

के इंदौर शिविर के संकल्प 'शून्य बजट प्राकृतिक (आध्यात्मिक कृषि) उत्पादक उपभोक्ता जागरूकता अभियान' को मध्यप्रदेश शासन कृषि कल्याण मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय कृषि मंत्री बिसेन जी, कृषि सचिव राजोरा जी, कृषि संचालक मीना जी सभी कृषि अधिकारी, नर्मदा समग्र के संकल्पित कर्मठ कार्यकर्ता, सुभाष पालेकर जन आंदोलन के सहयोगी इसके साक्षी बने। जिसमें 313 ब्लॉक से तीन से चार किसान, सभी आत्मा डायरेक्टर्स कृषि अधिकारी, मध्य प्रदेश के मॉडल किसान (1700 लोगों) ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। भाई साहब भारत सरकार में पर्यावरण मंत्री के दायित्व पर थे और उनके दृढ़ संकल्प का

> "मैं हूं तब भी, मैं ना रहूं तब भी, यह कृषि और कृषक अनुष्ठान होना चाहिए"

परिचय पुनः तब हुआ जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और हम सबने आग्रह किया कि आप ठीक होने के बाद इस आयोजन को करते हैं। परंतु उनका कहना था- ''मैं हूं तब भी, मैं ना रहूं तब भी, यह कृषि और कृषक अनुष्ठान होना चाहिए''। यह मेरा दूसरा अनुभव था। शायद उनको अपने निवृत्ति का आभास हो गया था। उन्हें तय समय सीमा में यह कार्यक्रम करवाया राजकोट से पालेकर जी दिल्ली होते हुए भोपाल आ रहे थे मेरे बेटे सचिन के साथ माननीय दवे जी को उनके निवास स्थान पर मिलने गए तब कार्तिक जी के साथ बंगले में जो प्राकृतिक सब्जियां उगाई थी खिलाई।

आज नया अध्याय गुजरात की आनंद की धरा से 16 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भारतीय प्राकृतिक कृषि को बल देने के उद्देश्य से जीरो बजट का यह जन आंदोलन भारतीय किसान की आत्मनिर्भर किसान योजना में बदल दिया।

करोड़ों किसान को अपने संदेश 'बेक टू बेसिक' का जड़ से जुड़ने अर्थ समझाया। आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव से संचुरी तक प्रकृति कृषि के कायाकल्प करेगा मिट्टी पर्यावरण जल की चिंता दूर करेगा खाद के आयात खर्च को कम करेगा स्वस्थ समृद्ध भारत बनेगा।

यह विधि कृषि मंत्री के नजरिए से गांव की परंपरा एवं नई तकनीक, एफ पी ओ के सहायता से सरकार के आत्मनिर्भर भारत में निर्णायक साबित होगा।

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाहजी ने आपने उद्बोधन में सहयोग, सहकार्य, स्वअवलंबन, स्व - अर्थ में सहकारिता मंत्रालय कृषि पूरक व्यवसाय व्यवस्थापन नीति किसान समृद्धि और विश्व ब्रांड बनानेमें सहायक होगा एक गाय से जिस तरह तीस एकड़ खेती कार्य होते हैं केंचवा कारखाना बनकर फ्री में खाद बनाकर खाद का खर्च कम करता हैं वैसे सहकारिता भी नया आयाम बनेगा।

गुजरात के राज्यपाल माननीय देवव्रत जी की अहम एवं निर्णायक भूमिका साबित हो रही है। जिन्होंने गुरुकुल में अपने जमीन पर इसके सूक्ष्म और वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान सत्य अहिंसा आधारित इस पद्धति को कसौटी पर प्रमाण के साथ प्रमाणित किया है। अब हिमाचल के साथ-साथ गुजरात राज्य में लागू किया है। डांग जिले को तो संपूर्ण प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया है। भारतीय कृषि के इस यज्ञ में आठ राज्यों के अनेकों अनेक साथियों का साथ भारतवर्ष के प्राकृतिक कृषि पालेकर तंत्र मॉडल कृषक, कृषि वैज्ञानिक डॉ. हरिओम जी, डॉ. बलजीत सारण जी डॉ डी. विनय कुमार जी और नीति आयोग के डॉ. राजीव कुमार जी दीक्षित भाई प्रफुल्ल भाई लोक भारती के साथी सभी राज्य के कृषि अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद।

अब मध्यप्रदेश शासन के साथ हम सभी मिलकर दूसरे पायदान पर नई ऊर्जा के साथ मा. प्रधानमंत्री, भारत सरकार, गुरुवर अनिल जी, कृषिऋषि पालेकर जी, माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास संस्कृति भारतीय परंपरा का 'पीएम कृषितीर्थ ग्राम' की निव रखते हैं।□

''तीर्थग्राम, कस्बा, नगर, महानगर कृषि आत्मनिर्भर भारत की डगर"

(लेखक - कृषितीर्थाचार्य संस्थापक, हरिधरा परिवार सुभाष पालेकर कृषि प्रचार प्रसार समन्वयक, प्रशिक्षक, मध्य प्रदेश, निमाड़ी गौ संवर्धन नस्ल सुधार एवं भारतीय पारंपरिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषितीर्थ ग्राम लोहारी, तहसील सनावद, जिला खरगोन म. प्र.)

वैश्विक मंच पर एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा भारत

❑ श्रीमती विभूति जोशी

2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर COP26 के रूप में जाना जाता है, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। COVID-19 महामारी के कारण एक वर्ष के लिए विलंबित, यह पार्टियों का 26वां सम्मेलन (COP) था। जैसा कि महामारी फैलने के बाद पहली बड़ी सभा से अपेक्षित था, यह COP चुनौतीपूर्ण था। COP की शुरुआत से पहले महीने में मेजबान देश में एक नई COVID-19 लहर के संकेतों के कारण भागीदारी के बारे में अनिश्चितता ने कई संभावित प्रतिभागियों को हतोत्साहित किया। चुनौतियों के बावजूद कई लोगों ने यात्रा की नई आवश्यकताओं, परीक्षणों की पूर्व बुकिंग और प्रतिदिन परीक्षण की परेशानी का सामना किया। सम्मेलन ने 200 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के साथ कई स्थानीय उत्साही लोगों को आकर्षित किया, हालांकि, बेतरतीब योजना और स्पष्टता की कमी के कारण COVID सावधानियों के प्रवेश और अवहेलना के लिए लंबी कतारें लगीं। इसके अतिरिक्त, कोटा में कमी, Side events के दौरान सीमित भागीदारी और तकनीकी गड़बड़ियों ने पर्यावरण को बहुत अधिक बहिष्कृत महसूस कराया।

CECOEDECON ने PAIRVI के सहयोग से एक अखिल भारतीय समूह MAUSAM के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। MAUSAM ने COP में कुछ सामूहिक कार्यक्रमों और प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया। मौसम के हिस्से के रूप में और CECOEDECON का प्रतिनिधित्व करते हुए, MISEREOR और CIDSE के सहयोग से आयोजित एक साइड इवेंट के दौरान मैंने 'समाजों को मौलिक रूप से बदलने के लिए जलवायु वित्त को बदलना- GCF फंडिंग का मामला' शीर्षक से आयोजित एक साइड इवेंट के दौरान समन्वय और इनपुट प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान मैंने, जमीनी स्तर के अनुभवों को मान्यता देने और कृषि संबंधी समाधानों का समर्थन करने के लिए सीधे किसानों को जलवायु वित्त मुहैया करना की प्राथमिकता की आवश्यकता प्रस्तुत की। इसके अलावा People's Summit में भी MAUSAM के बैनर तले दक्षिण एशियाई प्रतिभागियों के साथ 2 साइड इवेंट हुए। हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कुछ प्रमुख ग्रीन पार्टी (इंग्लैंड और वेल्स की ग्रीन पार्टी और स्कॉटलैंड की ग्रीन पार्टी) और लेबर पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठकें कीं।

एक ओर जहां गैर राज्य प्रतिभागियों के रूप में हमने नेटवर्किंग प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, हम आधिकारिक चर्चा के विकास का भी उत्सुकता से पालन कर रहे थे क्योंकि यह COP अनुच्छेद 6 सहकारी तंत्र (बाजार और गैर-बाजार आधारित दृष्टिकोण सहित), राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं के लिए सामान्य समय सीमा और बेहतर पारदर्शिता तंत्र के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप/सारणी सहित पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने वाला था। इसके अलावा, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, और हानि और क्षति (वित्त सुविधा का निर्माण) के संबंध में अपेक्षाएं थीं। जलवायु वित्त और अनुकूलन वित्त भी प्रमुख मुद्दे थे जिन पर परिणाम अपेक्षित थे। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण था, वह था जलवायु वित्त और 100 बिलियन अमरीकी डालर का वितरण।

विश्व दर्शकों की सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा शमन महत्वाकांक्षा पर औद्योगिक देशों की एक मजबूत प्रतिक्रिया थी। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि COP 26 से पहले प्रतिबद्ध एनडीसी 1.5 डिग्री से नीचे तापमान में वृद्धि को सीमित करने में असमर्थ हैं और उत्सर्जन को कम करने की अपेक्षाओं के विपरीत, वैश्विक उत्सर्जन में 2030 तक 16 की वृद्धि होने की संभावना है। हम और दुनिया, 1.5 लक्ष्य को बचाने के लिए CoP26 से त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे।

सामान्य अपेक्षा के अलावा, हम

प्रकृति आधारित समाधानों के विषय पर भी ध्यान रखे हुए थे। यहां हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रकृति आधारित समाधानों को मानक परिभाषा (और सिद्धांतों) की आवश्यकता है। वर्तमान में उन्हें जो मजबूत समर्थन मिल रहा है, वह कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से ध्यान हटा रहा है।

महत्वाकांक्षी एजेंडे रखते हुए जहां COP26 कुछ मजबूत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सफल रहा, वहीं यह कई महत्वपूर्ण अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। सम्मेलन के प्रमुख परिणाम थे-

- **1.5 डिग्री लक्ष्य को पहचानना:** इस CoP से पहले, बहुत से लोगों, देशों, वैज्ञानिक समुदाय ने 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि लक्ष्य को छोड़ दिया था। हालाँकि, COP 26 ने इसे जीवित रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रतिबद्धता का कार्यों में परिवर्तन अभी भी अनुपस्थित है।
- **यह स्वीकारा गया कि कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन को त्यागने की जरूरत है:** हालांकि 2030 तक कोयले को खत्म करने के लिए केवल 40 विषम देशों ने हस्ताक्षर किए (2030 तक विकसित देश, 2040 तक विकासशील) यह एक सही दिशा की तरफ अच्छा कदम है। हालांकि, कई बड़े खिलाड़ियों को अभी भी इन प्रतिबद्धताओं में अपनी आवाज जोड़नी है।
- **अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य:** वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पर दो साल के ग्लासगो-शर्म अल शेख कार्य कार्यक्रम को देखकर अच्छा लगा लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
- **वनों की कटाई और भूमि प्रबंधन पर ग्लासगो घोषणा:** यह एक बड़ा विकास था, लेकिन प्रभावशीलता कार्रवाई में निहित होगी।
- **मीथेन प्रतिज्ञा:** यह एक और स्वागत योग्य खबर है। लेकिन मजबूत लक्ष्यों और नाइट्रस ऑक्साइड को शामिल करने के साथ इसके और अधिक महत्वाकांक्षी होने की गुंजाइश फिर से बनी हुई है।
- **परिवहन उत्सर्जन:** परिणाम दस्तावेज़ में 2030 तक ICE यात्री कारों को समाप्त करना और पार्टियों से कुछ प्रतिबद्धताओं के साथ ICE ट्रक और बसें शामिल हैं।

सम्मेलन में भारत एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा। भारत ने एक बार फिर जिम्मेदारियों के अपने न्याय हित हिस्से से अधिक लेने की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। ग्लासगो में पार्टियों के 26वें सम्मेलन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2070 तक Net Zero (शुद्ध-शून्य) उत्सर्जन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 2030 तक अपनी ऊर्जा मांग का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करते हुए, भारत ने अब से 2030 तक 1 बिलियन टन अनुमानित उत्सर्जन को कम करने और 2030 तक 2005 के स्तर पर कार्बन की तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके अलावा, भारत ने ब्रिटेन के साथ छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स पहल की शुरुआत की, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बेहद संवेदनशील हैं।

भारत विकासशील दुनिया के प्रति अन्याय के विषय पर भी मुखर था। और देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जलवायु वित्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'संतुलन की कमी' और तात्कालिकता की ओर इशारा किया। उम्मीद है कि कई मोर्चों पर भारत की मजबूत प्रतिबद्धता, विकसित देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ उचित प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करेंगी। भारत को अपना ध्यान घरेलू स्तर पर ऊर्जा पहुंच बढ़ाने, चरम जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और आपात स्थिति के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। □

(लेखक -विकास और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सिकोईडिकोन) कार्यरत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ें मंचों पर भागीदारी)

नदी एंबुलेंस - अनुभव कथन

मां नर्मदा के तटीय स्थलों के ग्रामों में बसे लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा करते हुए गुजरात प्रांत के छोटे उदयपुर जिले के ग्राम हाफेश्वर नामक स्थल से सेवा कार्य आरंभ कर मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले का अंतिम ग्राम आकडीया से लेकर ग्राम झंडाना तक सेवा देकर समापन शाम किया जाता था। मां नर्मदा के तट स्थित लगभग 40-42 फलियों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नर्मदा समग्र द्वारा संचालित रिवर एंबुलेंस से दी जाती है।

❑ गोपाल प्रजापति

श्री अनिल माधव दवे जी द्वारा नर्मदा समग्र नामक संस्था के माध्यम से सरदार सरोवर के बैक वाटर से घिरे वनवासियों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रिवर एंबुलेंस प्रारंभ की। ऐसे सेवाभावी लोग विरले ही इस भूमि पर जन्म लेते हैं। मैं गोपाल प्रजापति, स्व श्री अनिल माधव दवे जी भाई साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए स्वअनुभव के कुछ अंश लिख रहा हूं। मैं स्वयं नदी एंबुलेंस पर कुछ वर्ष रहा हूं और इस क्षेत्र का निवासी हूं।

श्री अशोक जी पाटीदार जब जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक के दायित्व का निर्वहन करते हुए डही आए उस दौरान मेरा एक पत्रकार की हैसियत से मेरा उनसे से परिचय हुआ। श्री पाटीदार जी द्वारा प्रवास के दौरान किए गए जन अभियान परिषद के कार्य को मैंने दैनिक स्वदेश में प्रकाशित किया। तभी से मेरे और श्री पाटीदार जी के जीवित संपर्क बने रहे और हम पत्रकार एवं अधिकारी की जगह मित्र हो गए। कुछ समय उपरांत पाटीदार जी नर्मदा समग्र के प्रांतीय समन्वयक बने। इस दौरान भी हम अकसर पर्यावरण को लेकर चर्चा करते रहते थे।

श्री पाटीदार जी पर्यावरण प्रिय व्यक्ति हैं। पाटीदार जी घाट सफाई को लेकर सभी को प्रेरित करते, मैं भी वन औषधि को महत्व देने, अकसर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन औषधि युक्त तथा आदिवासी समाज की आजीविका एंव स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते रहता था। इस दौरान नर्मदा समग्र द्वारा संचालित की जाने वाली रिवर एंबुलेंस के समन्वयक के दायित्व हेतू मेरा चयन किया गया। मैंने अपनी अनेक वर्षों पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की दुकान का परित्याग कर नदी एंबुलेंस में वंचितों की सेवा हेतु चला गया। नदी एंबुलेंस सप्ताह में पांच दिन सरदार सरोवर के बैक वॉटर से घिरे मां नर्मदा के किनारे वाले पहाड़ों पर बसे आदिवासियों के स्वास्थ्य की निशुल्क सेवा देती आ रही है विगत छः-सात वर्षों से। इसमें एक डॉक्टर, बोट चालक, एक सहायक तथा समन्वयक, इस प्रकार चार से पांच व्यक्तियों की टोली कार्यरत रहती है। एंबुलेंस का केंद्र अलीराजपुर जिले की सोंडवा तहसील का ग्राम ककराना नामक स्थल पर है। वहां से बुधवार प्रातः धार जिले के नर्मदा नदी के किनारे बसे विभिन्न ग्रामों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देते हुए ग्राम धरमराय नाम स्थल पर रात्रि विश्राम कर गुरुवार वहीं से दक्षिण तट स्थित बड़वानी जिले के ग्राम बोरखेड़ी नामक स्थल से प्रारंभ कर शाम को पुनः ककराना रात्रि विश्राम किया जाता। शुक्रवार ककराना एंव वालपुर हाट बाजार होने के कारण एंबुलेंस को स्थाई रूप से शुक्रवार को एक दिन की सेवा ग्राम ककराना मैं ही देना रहती है। क्योंकि दक्षिण तट स्थित मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के अनेकों ग्रामों के लोग अलीराजपुर जिले के ग्राम वालपुर नामक स्थल पर साप्ताहिक हाट बाजार में खरीदी बिक्री करने हेतु पहुंचते हैं।

उन लोगों का मां नर्मदा के किनारे

ककराना में ही निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। शनिवार प्रातः ककराना से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर महाराष्ट्र प्रांत के नंदुरबार जिले के मां नर्मदा के तटीय स्थलों के ग्रामों में बसे लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा करते हुए गुजरात प्रांत के छोटे उदयपुर जिले के ग्राम हाफेश्वर नामक स्थल पर रात्रि विश्राम किया जाता था। वही रविवार प्रातः ग्राम हाफेश्वर से सेवा कार्य आरंभ कर मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले का अंतिम ग्राम आकडीया से लेकर ग्राम झंडाना तक सेवा देकर समापन शाम किया जाता था। मां नर्मदा के तट स्थित लगभग 40-42 फलियों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नर्मदा समग्र द्वारा संचालित रिवर एंबुलेंस से दी जाती आ रही है।

अपने कार्यकाल में पटेल फलीया नामक स्थल पर एक बालिका को लगभग रात्रि आठ बजे सांप ने काटा लिया था। उसे हमने व हमारी टीम ने जान की परवाह किए बगैर अंधेरी रात में एक घंटे पानी में एंबुलेंस से सफर कर उसे हाफेश्वर पहुंचाया वहां से परिजनों द्वारा उस बालिका को उपचार हेतु गुजरात प्रांत के उदयपुर जिला मुख्यालय ले जाया गया और वहां उपचार के पश्चात उस बालिका की जान बच गई।

एक और घटना है जिसमें अलीराजपुर जिले के ग्राम अंजनवारा में लगभग 14 वर्षीय बालक ने भूलवश कपास में छिड़काव करने वाली रोंगर नामक दवाई पीली थी। उसे भी हमने प्राथमिक उपचार प्रदान कर नदी एंबुलेंस के सहयोग से महाराष्ट्र प्रांत जिला नंदुरबार के ग्राम भुसीया घाट पर मात्र दो से तीन घंटे में पहुंचाया। वहां से उस बालक के परिजनों द्वारा उपचार हेतु महाराष्ट्र के धड गांव नामक स्थल पर ले जाया गया और उपचार के पश्चात व स्वस्थ हो गया। आज भी ग्राम अंजनवारा के आदिवासी बालक के माता-पिता व अन्य परिजन तथा ग्रामवासी जन नर्मदा समग्र का आभार मान रहें है।

इस एंबुलेंस के प्रारंभिक अवस्था के दौरान टीम को भारी मशक्कत का सामना करना पढ़ा था। मैं स्थानीय क्षेत्र का निवासी होने से क्षेत्रीय भाषा बोलना एवं समझना जानता हूं साथ ही मुझे वन औषधियों के संदर्भ में भी जानकारी थी। इसके उपरांत जब हम रिवर एंबुलेंस के माध्यम से इन लोगों के पास पहुंचते थे वैसे ही यह लोग भाग खड़े होते और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाते थे। हम इन्हें क्षेत्रीय भाषा में चर्चा कर जानकारी देते थे कि हम आपकी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करने के लिए यहां तक आए हैं। इस दौरान भी यह एक या दो लोग डरते-डरते एंबुलेंस तक पहुंच पाते थे। इस एंबुलेंस को संचालित करने के लिए हमने इन लोगों को से निवेदन करते हुए कहा था कि हम यहां से गुजरेंगे अगर आप व आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, ता नर्मदा के किनारे पर आकर कपड़ा हिला देना हम आप तक पहुंच जाएंगे और वहां के निवासरत लोगों ऐसा ही करते रहे। कुछ समय व्यतीत होने से परिचय बढ़ा और यह लोग समझ गए कि यह हमारे स्वास्थ्य रक्षक है। फिर प्रत्येक गांव में एक स्टेशन और समय निर्धारित किया गया। आज भी वहां लोग विजिट के दौरान आकर बैठ जाते हैं, पानी में तैरते दवाखाने द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

प्रथम अवस्था में यहां अनेक गरीब लोगों के पास अपना स्वयं के शरीर को ढकने के लिए व्यवस्थित वस्त्र तक नहीं थे। तो हमने नगर के लोगों से इस विषय में चर्चा की और पुराने अच्छे कपड़े ले जाकर जरूरतमंदो को देना आरंभ किया। समीप के नगरों, एंबुलेस पर आए लोगों एवं संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा आज भी समय-समय पर इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं जैसे कपड़े, खाद्य सामग्री, औषधी, इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही बच्चों के पठन-पाठन हेतु सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है और वर्तमान में तीन संस्कार केंद्रों का भी संचालन स्थानीय लोगों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं/संस्था के सहयोग से आंरभ हुआ है।

मैं तो बस यही कहता हूं/मानता हूं की अंत में यह पुण्य ही साथ जाने वाला है अन्य कुछ नहीं। मैं ऐसे अनुकरणीय कार्य का हिस्सा रहा और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं भी कुछ समय तक प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर पाया। आज भी कार्यकर्ता होने के नाते जुड़ा हूं और समय-समय पर अपना योगदान प्रदान करता रहता हूं। □

(लेखक - पत्रकार, समाज सेवक, एवं नदी एम्बुलेंस के पूर्व समन्वयक)

पर्यावरण पंचकोशी यात्रा

17 दिसम्बर 2021 को पर्यावरण पंचकोसी यात्रा स्थान - डेम घाट से ईमली कुटी घाट

दिनाँक 19 दिसम्बर को नर्मदा समग्र घाट इकाई मुअर घाट टीम द्वारा एक दिवसीय पर्यावरण पंचकोसी यात्रा बरमकुंड घाट से सा कल घाट की गई ।

27, 28, 29 नवम्बर को झांसी घाट से करेली खुर्द तक तीन दिवसीय यात्रा नर्मदा समग्र टीम एवं माँ नर्मदा सेवा समिति की टोली ने की ।

दिनाँक 19 दिसम्बर को नर्मदा समग्र घाट इकाई मुअर घाट टीम द्वारा एक दिवसीय पर्यावरण पंचकोसी यात्रा बरमकुंड घाट से सा कल घाट की गई ।

स्वास्थ्य शिविर आयोजन

ग्राम भादल एवं जलसिंधी

ग्राम भादल एवं जलसिंधी

ग्राम भिताड़ा एवं भादल

ग्राम भिताड़ा एवं भादल

ग्राम भिताड़ा एवं भादल

ग्राम भिताड़ा एवं भादल

सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में नर्मदा समग्र द्वारा संचालित नदी एम्बुलेंस द्वारा भाऊ फाउंडेशन संस्था के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुंबई से आए डॉ. अनिल पाटिल जी व नदी एम्बुलेंस के चिकित्सक ने मिलकर ग्राम भादल एवं जलसिंधी के 95 ग्रामवासियों (वनवासियों) की चिकित्सा जाँच कर उन्हें दवा प्रदान की। साथ ही ग्राम खाड़िया, सादरी और जलसिंधी में 210 वनवासी ब%चों को ऊनी वस्त्र, पदवेश एवं मिठाई का वितरण किया। साथ ही दिनांक 23.10.2021 को ग्राम भिताड़ा एवं भादल (तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर) में पुणे से अश्वनी दीदी के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुणे के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. विकास आलूरे, डॉ. प्रीति आलूरे एवं डॉ. ओमकार आलूरे ने लगभग 113 वनवासी ब%चों, महिलाओं और पुरुषों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई प्रदान की।

संस्मरण

कल जरा हड़बड़ी थी इसलिए कुछ ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि घर में दिवाली की साफ सफाई का काम लगा हुआ है और मेरे ऑफिस की ही सफाई हो रही थी जहां तक बापू की बात है तो मेरे पिताजी के भी हीरो रहे पिताजी ने खूब लिखा है गांधी जी के ऊपर और गांधी जी के हाथ का लिखा हुआ पोस्टकार्ड जिसमें उन्होंने अपने हाथ से भी एड्रेस किया हमारे घर का वह भी रखा है कुछ साल पहले मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पर मेरे दादाजी बड़े क्रांतिकारी थे गांधीजी का जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों के लिए

जो ठेकेदारी करते थे वह छोड़ दी थी वे अक्सर हरिजनों को अपने घर में खाना खाने बुलाया करते थे मैं जब हाफ पेंट पहनता था तो मैंने अपनी आंखों से मैला ढोने वालों को देखा है उस समय बहुत कम लोगों के यहां सेप्टिक वाला शौचालय हुआ करता था।

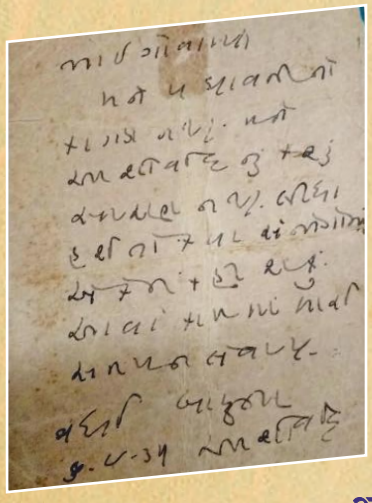

ऐसे मेला उठाने वालों को आप अपने घर में बुलाकर खाना खिलाए सोचो कितनी बड़ी बात है बापू की बताए राह पर चलना उस समय भी कठिन था और आज भी मेरी कोशिश है कि कम से कम मैं झूठ ना बोलूं, किसी का अहित ना करूं। वैसे अभी प्रस्थान करने का समय तो नहीं आया है वानप्रस्थ पर चल रहा हूं। चिड़िया, जानवर प्रकृति दिख रही है और कोशिश करता हूं दूसरों को भी दिखाओ कहां तक सफल हुआ नहीं जानता, लेकिन जटायु की असफलता रावण की सफलता से हजार गुना बेहतर थी (पिताजी का डायलॉग मारा है) और क्यों ना करूं आज उनका जन्मदिन जो है।

(- नीरज वेगड़ की फेसबुक वॉल से)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन

बेहतर कल के लिए हर-घर नल से जल

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

"मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुँचाने का अभियान पूरी गति से चल रहा है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता वाले ग्राम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 4258 ग्राम इस श्रेणी में शामिल, जिनके 48 लाख 69 हजार से अधिक परिवार स्वच्छ पेयजल की सुविधा पा रहे हैं। वर्ष 2024 तक 122 लाख ग्रामीण परिवारों के घर तक जल पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत सभी जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये जाएं"

2024 तक 'हर घर जल' वाला राज्य बनाने की योजना

जल-प्रदाय योजनाओं के लिए

30 हजार 668 करोड़

रुपए स्वीकृत

पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था

39.62% ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन से पेयजल की उपलब्धता

स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में भी नल कनेक्शन से दिया जा रहा है पेयजल

D-16123/21

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्री करण सिंह कौशिक द्वारा नियो प्रिंटर्स, 17 बी-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल एवं नदी का घर सीनियर एम.आई.जी.-2 अंकुर कॉलोनी, पारूल अस्पताल के पास शिवाजी नगर, भोपाल-462016 से प्रकाशित। संपादक कार्तिक सप्रे। फोन नं. : 0755-2460754